

घाटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 338- शनिवार 10- अक्टूबर 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये RNI Reg.No.-CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीवन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर विपक्षी गठबंधन का लगातार चौथे दिन प्रदर्शन

राष्ट्रपति ने वोट चोरी से इनकार नहीं किया,हमसे सबूत मांगे : राहुल गांधी

नई दिल्ली,09 अक्टूबर 2026। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्षी गठबंधन ने शुक्रवार को लगातार चौथे दिन प्रदर्शन और मार्च निकाला। सबसे पहले पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में एक घंटे मीटिंग की। इसके बाद सांसदों ने संसद से राष्ट्रपति भवन तक पैदल मार्च किया। राहुल, ममता, खड़गे समेत 10 सांसदों का डेलीगेशन राष्ट्रपति से मिला। बाकी सांसदों ने विजय चौक पर धरना दिया। मीटिंग से बाहर आकर राहुल ने कहा कि पूरा देश जानता है कि देश में वोट चोरी हो रही है। राष्ट्रपति ने भी इससे इनकार नहीं किया। अब हम सोमवार को सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। विपक्षी सांसदों ने पिछले 4 दिनों में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ तीसरा मार्च निकाला है। इससे पहले 6 अक्टूबर को सेव डेमोक्रेसी मार्च निकाला था। फिर 7 मार्च को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के लिए गए थे। रास्ते में रोक दिया गया। 8 अक्टूबर को कर्नाट प्लेस से राजघाट तक मार्च निकाला था। चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर जारी राजनीतिक विवाद के बीच इंडी गठबंधन ने शुक्रवार को अपना विरोध तेज करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और उन्हें जापन सौंपा। विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने चुनावी प्रक्रिया से जुड़े अपने सवालों और चिंताओं को राष्ट्रपति के सामने रखा। कांग्रेस अध्यक्ष और राजसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के बाद कहा कि विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने उन्हें जापन सौंपकर कथित वोट चोरी के मुद्दे पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा- हमने पिछले चार दिनों से चल



राहुल बोले...ज्ञानेश कुमार वोट चोरी करा रहे हैं

राहुल ने कहा- राष्ट्रपति से मुलाकात अविवशनीय रही। हमने इलेक्शन चोरी-वोट चोरी के बारे में बताया तो राष्ट्रपति ने इससे खंडन नहीं किया। उन्होंने कहा कि वे इसके बारे में सोचेंगी और एक्शन लेंगी। राष्ट्रपति ने हमसे सबूत मांगे हैं। ज्ञानेश कुमार ने भारत लोकतंत्र को तबाह किया है। ज्ञानेश कुमार वोट चोरी करा रहे हैं।

गौरव गोगोई बोले...वोट का अधिकार बचाना जरूरी

कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, हम यह हर व्यक्ति के वोट के अधिकार को बचाने के लिए कर रहे हैं,चाहे उसकी विचारधारा कुछ भी हो। चाहे वह हमारा समर्थक हो या आलोचक। मेरा मानना है कि जो लोग हमारी पूरी चुनावी प्रक्रिया को बदनाम करने और उसमें गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं,वे देशद्रोही हैं।

रेह आंदोलन और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से जुड़े कथित गंभीर मामले को राष्ट्रपति के सामने उठाया। हमने उनसे मांग की है कि ईवीएम के बजाय बलेट पेपर से चुनाव कराए

जाएं। खड़गे ने बताया कि राष्ट्रपति ने वोट चोरी के आरोपों से जुड़े सबूत मांगे हैं। विपक्ष फिलहाल सबूत जुटा रहा है और उन्हें राष्ट्रपति को सौंपेगा।



ममता बनर्जी बोलीं...राष्ट्रपति ने जांव का भरसा दिया...

पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के बाद कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति को एक जापन सौंपा है। राष्ट्रपति ने मामले की जांच करने और पूरे विवरण को देखने की बात कही है। उन्होंने संबंधित मामले के सबूत भी मांगे हैं, जिन्हें हमें उन्हें जल्द ही सौंप देंगे। ममता बनर्जी ने कहा कि देश इस मुद्दे को लेकर चिंतित है। इस मुद्दे पर हमने राष्ट्रपति से संविधान के संरक्षक के रूप में लोकतंत्र की रक्षा के लिए उचित कदम उठाने की अपील की। राष्ट्रपति की प्रतिक्रिया पॉजिटिव थी और उन्होंने मामले की जांच करने का आश्वासन दिया है। ममता ने कहा...हमें सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। उन्होंने कहा कि वह इसकी जांच करेंगी और पूरी जानकारी देखेगी। उन्होंने सबूत मांगे हैं,जिन्हें भेजने की बात हमने कही है। देश इस मुद्दे को लेकर बहुत चिंतित है। आप संविधान की संरक्षक हैं, इसलिए लोकतंत्र की रक्षा के लिए उचित कदम उठाने चाहिए। उन्होंने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और कहा कि वह मामले की जांच करेंगी।

खेड़ा बोले...राष्ट्रपति भवन लोकतंत्र का आखिरी प्रहरी

कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने कहा, राष्ट्रपति भवन लोकतंत्र का आखिरी प्रहरी है। हम अपनी गृहार इसी आखिरी प्रहरी तक ले जा रहे हैं और उनसे इसे बचाने की अपील कर रहे हैं। लोकतंत्र और संविधान अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। अब इन्हें बचाने की जिम्मेदारी राष्ट्रपति की है।

शिवकुमार बोले...हम संविधान की रक्षा करना चाहते हैं...

कर्नाटक सीएम डीके शिवकुमार ने कहा, हम संविधान की रक्षा करना चाहते हैं और हर वोटर के अधिकार की रक्षा करना चाहते हैं। इस सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए। उन्होंने जिन-जिन चुनावों में जीत हासिल की है, वे सभी अवैध हैं। हम बलेट पेपर की व्यवस्था फिर से लागू करना चाहते हैं और चुनाव आयुक्त को हटाया जाना चाहिए। कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने कहा,हम शांतिपूर्वक सभी के पास जा रहे हैं और कह रहे हैं कि चुनाव आयोग द्वारा की जा रही इस वोट चोरी को रोकना जाए।

प्रदर्शन की इजाजत न मिलने पर बोले दीपके ‘हमारा आंदोलन होकर रहेगा’

नई दिल्ली,09 अक्टूबर 2026। कॉंग्रेस जनता पार्टी (सीजेपी) के विरोध-प्रदर्शन से एक दिन पहले, शुक्रवार को इसके संस्थापक अभिजीत दीपके ने केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि अगर सरकार युवाओं से डरती है,तो उसे पूरे देश को ही बंद कर देना चाहिए। यह बयान 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय राजधानी आने-जाने वाली ट्रेनों के रद्द होने के बाद आया है। इसके साथ ही कहा कि हमारा आंदोलन होकर रहेगा। सीजेपी ने चुनाव आयोग की ओर से मतदाता सूची के ‘स्पेशल इंटेसिव रिविजन’ (एसआईआर) में भारी गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए, मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर शनिवार को दिल्ली के जंतर-मंतर पर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करने का आह्वान किया है। कॉंग्रेस जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा, ‘हमारा आंदोलन होकर रहेगा। जंतर-मंतर विरोध प्रदर्शन के लिए तय जगह है। अनुच्छेद 19 विरोध करने का मौलिक अधिकार देता है तो, फिर इजाजत लेने की क्या जरूरत है? क्या उन्होंने 13 करोड़ वोट हटाने से पहले इजाजत ली थी? आप चाहते हैं कि हम चुनाव में धांधली करने वालों के खिलाफ आवाज न उठाएं? ऐसा नहीं हो सकता। देश ऐसे नहीं चल सकता। देश को बचाने के लिए हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। वहीं, रेलवे बोर्ड ने शुक्रवार को 10 अक्टूबर को सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन स्टेशनों पर पहुंचने वाली कुछ मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द कर दिया। दिल्ली पुलिस ने



प्रदर्शन से पहले दिल्ली पुलिस का खुला पत्र...जनता के लिए लिखा-आपकी आवाज आपका हक है,आपकी सुरक्षा हमारा फर्ज

कॉंग्रेस जनता पार्टी (सीजेपी) के मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग संबंधी प्रदर्शन से पहले दिल्ली पुलिस ने जनता से अनोखे अंदाज में अपील की है। दिल्ली पुलिस ने एक खुला पत्र जारी किया है, जिसमें लिखा है कि युनिफॉर्म (वर्दी) के पीछे भी एक इंसान है,जिसका अपना परिवार है। दिल्ली पुलिस ने पत्र में लिखा, ‘प्रिय नागरिकों, आपकी आवाज आपका हक है और आपकी सुरक्षा हमारा फर्ज है। युनिफॉर्म (वर्दी) के पीछे भी एक इंसान है,जिसका अपना परिवार है,

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) से 57 मेट्रो स्टेशन बंद करने का आग्रह किया है ताकि विरोध प्रदर्शन में शामिल होने आ सकने वाले युवाओं की आवाजाही को रोकना जा सके।

नंदीग्राम में भाजपा कैडिडेट ने सीएम शुभेंद्रु का रिकॉर्ड तोड़ा

उपचुनाव में 1.22 लाख वोटों से जीत,पुडुचेरी में एनडीए,तमिलनाडु की दोनों सीटें टीवीके जीती

नई दिल्ली,09 अक्टूबर 2026। प. बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी की 5 विधानसभा सीटों और असम की एक लोकसभा के उपचुनाव के नतीजे शुक्रवार को आ गए। पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर सीटें भाजपा ने जीत ली है। वहीं तमिलनाडु की दो सीटों पर टीवीके ने कब्जा किया। उधर, पुडुचेरी की एक विधानसभा सीट पर एनडीए ने जीत हासिल की। वहीं, असम के नगांव लोकसभा सीट पर भाजपा आगे चल रही है। नंदीग्राम सीट पर बीजेपी प्रत्याशी हसीरानी रथ 122753 वोटों से जीत गई हैं। उन्हें कुल 164427 वोट मिले।हसीरानी ने इस सीट पर सीएम शुभेंद्रु अधिकारी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हसीरानी ने 1,22,753 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। यह 1967 के सीट के अस्तित्व में आने के बाद जीत का सबसे बड़ा अंतर है। इससे पहले सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड 2016 में शुभेंद्रु अधिकारी के नाम था। तब उन्होंने टीएमसी के टिकट पर सीपीआई के अब्दुल कबीर शेख को 81,230 वोटों से हराया था।

जीत के बाद हसीरानी रथ ने कहा... बंगाल में जनता ने भाजपा पर भरोसा जताया : नंदीग्राम में जीत के बाद भाजपा उम्मीदवार हसीरानी रथ ने कहा, ‘मुख्यमंत्री के रूप में सिर्फ पांच महीने के कार्यकाल में उनकी सरकार ने नंदीग्राम से लेकर पहाड़ी



हसीरानी बोलीं- यह जीत शुभेंद्रु के मुख्यमंत्री होने का नतीजा

उपचुनाव के नतीजों पर नंदीग्राम से बीजेपी की उम्मीदवार हसीरानी रथ ने कहा, ‘यह रिकॉर्ड जीत सुवेंद्रु अधिकारी के मुख्यमंत्री होने का नतीजा है। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के समय में हमारे कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न किया जाता था और उन्हें वोट नहीं डालने दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। नंदीग्राम सबसे अशांत इलाका था, मुख्यमंत्री के कारण यहां लोकतंत्र फिर से बहाल हुआ है। इस बार चुनाव में कोई खून-खराबा नहीं हुआ; न तो बम फेंके गए और न ही गोलियां चलाई गईं।’

और जंगलों वाले इलाकों तक विकास कार्य जारी रखे हैं। राज्य में कई लाख करोड़ रुपए का कर्ज होने के बावजूद सरकार राज्य के विकास के लिए काम कर रही है। जनता ने उनकी सरकार ने नंदीग्राम से लेकर पहाड़ी

स्टालिन बोले...उपचुनाव लोकतंत्र की खुली हत्या थे : तमिलनाडु की दोनों सीटें हारने के बाद डीएमके के एमके स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु उपचुनाव लोकतंत्र की खुली हत्या थे।

मोदी बोले...उपचुनावों की जीत दिखाती है कि लोगों का हमसे गहरा जुड़ाव

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को असम, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी के उपचुनावों में बीजेपी-एनडीए को आशीर्वाद देने के लिए लोगों का आभार जताया और कहा कि यह जीत एक बार फिर दिखाती है कि लोगों का गठबंधन के सुशासन के एजेंडे से ‘गहरा जुड़ाव’ है।

रेजीनगर विधानसभा सीट 75,000 से ज्यादा वोटों से जीती : बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले की रेजीनगर विधानसभा सीट 75,816 वोटों के अंतर से जीती। मुस्लिम-बहुलता वाली इस सीट में यह बीजेपी की एक बड़ी कामयाबी है। बीजेपी उम्मीदवार सरकार को 1,29,914 वोट मिले। उन्होंने आम जनता उन्मथन पार्टी के उम्मीदवार गुलाम नबी आजाद को हराया,जिन्हें 54,098 वोट मिले। बीजेपी को लगभग 63.14% वोट मिले,जबकि आजाद को 26.29% वोट मिले। रेजीनगर में लगभग 70% मुस्लिम मतदाता हैं और यहां पारंपरिक रूप से टीएमसी, कांग्रेस और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के बीच मुकाबला होता रहा है।

गुजरात के कच्छ में ट्रक और बोलeros के बीच टक्कर में सात मजदूरों की मौत

भुज/अहमदाबाद, 09 अक्टूबर 2026। गुजरात के कच्छ में आज सुबह ट्रक और बोलeros के बीच टक्कर में सात मजदूरों की मौत हो गई। बोलeros गाड़ी में 15 से ज्यादा मजदूर सवार थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि केबिन में फंसे लोग दर्द से कराह रहे थे। वहां आसपास मौजूद लोग यह मंजर देख आवाक थे। कच्छ जिले में आज मजदूरों को ले जा रही एक बोलरो गाड़ी खावड़ा के पास आईआईएफ के रास्ते से गुजर रही थी। इसी दौरान एक ट्रक ने बोलरो को जोरदार टक्कर मार दी। यह टक्कर इतनी जोरदार थी कि इस हादसे में सात मजदूरों की मौत हो गई। बोलरो में 15 से ज्यादा मजदूर सवार थे, जबकि कुछ घायल हो गए हैं। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। अभी घायलों की संख्या और उनकी हालत के बारे में अभी अधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। हादसे के बाद उन्हें खवड़ा से भुज ले जाया गया। उन्हें पोस्टमॉर्टम के लिए ले जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस हादसे से पूरे इलाके में मातम छ गया। पुलिस जांच पूरी होने के बाद दुर्घटना की आधिकारिक जानकारी और घायलों की हालत के बारे में पता चल सकेगा।



उप कैबिनेट का फैसला : प्रधानमंत्री मोदी के नाम से जाना जाएगा जेवर एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा जेवर एयरपोर्ट

लखनऊ, 09 अक्टूबर 2026। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक हुई। जिसमें जेवर एयरपोर्ट का नाम बदलने के फैसले को मंजूरी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जेवर एयरपोर्ट का नाम बदलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया है। लोक भवन में आज आयोजित कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया सेंटर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेवा कार्यों का हार्दिक अभिनंदन करती है। वे उत्तर प्रदेश से ही जनप्रतिनिधि होकर देश का नेतृत्व कर रहे हैं। कैबिनेट ने जेवर एयरपोर्ट का नाम बदल कर नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश का रिश्ता बेहद आत्मीय है। काशी और मां गंगा से आरंभ हुआ आत्मीय सम्बंध समय के साथ निरंतर गहरा हुआ और आज राज्य के सर्वांगीण कायाकल्प का आधार बना है।

कौशल प्रशिक्षण संस्थान आईआईटी और आईआईएम से कम नहीं : पीएम मोदी

नई दिल्ली,09 अक्टूबर 2026। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि कौशल प्रशिक्षण संस्थानों का महत्व किसी भी तरह से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और भारतीय प्रबंधन संस्थानों से कम नहीं है। उन्होंने युवाओं से बदलती तकनीक के अनुरूप लगातार नए कौशल सीखने और अपनी क्षमताओं को उन्नत करने का आह्वान किया। मोदी ने यहां अपने आवास सात, लोक कल्याण मार्ग पर शंघाई में आयोजित 48वीं विश्व कौशल प्रतियोगिता में भाग लेने वाली भारतीय टीम के प्रतिनिधियों से बातचीत की। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिभागियों को



बधाई दी और उन्हें देश में कौशल विकास का दूत बनने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यावहारिक कौशल भी शैक्षणिक डिग्रियों जितने ही महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने युवाओं से अंतरराष्ट्रीय बाजार की जरूरतों के अनुरूप कौशल विकसित करने और उपरती प्रौद्योगिकियों के साथ

तालमेल बिठाने को कहा। मोदी ने कहा कि भारत को कुशल मानव संसाधन का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए युवाओं, सरकार और प्रशिक्षण संस्थानों को मिलकर काम करना होगा। उन्होंने प्रतिभागियों से प्रतियोगिता के दौरान प्राप्त अनुभव और सुझाव सरकार के साथ साझा करने का आग्रह किया, ताकि देश

को कौशल प्रशिक्षण व्यवस्था को और बेहतर बनाया जा सके। प्रतिभागियों ने प्रतियोगिता के दौरान नए उपकरणों,सॉफ्टवेयर, तकनीकी प्रणालियों और कार्य प्रक्रियाओं के अनुरूप खुद को ढालने के अनुभव साझा किए। उन्होंने कौशल विकास के लिए सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों का भी उल्लेख किया। शंघाई में 22 से 27 सितंबर तक आयोजित 48वीं विश्व कौशल प्रतियोगिता में भारत 10 वें स्थान पर रहा। भारतीय दल ने छह रजत पदक और उत्कृष्टता के 20 पदक जीते। प्रतियोगिता में भारत की ओर से अब तक का सबसे बड़ा 70 सदस्यीय दल 63 कौशल श्रेणियों में शामिल हुआ था।

कपूरथला में बनी वंदे भारत ट्रेन का मथुरा-नागदा खंड पर 180 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से सफल परीक्षण

नई दिल्ली,09 अक्टूबर 2026। पंजाब के कपूरथला स्थित रेल कोच फैक्टरी (आरसीएफ) में निर्मित 16 डिब्बों वाली वंदे भारत ट्रेन का मथुरा-नागदा रेलखंड पर 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सफल परीक्षण किया गया है। रेलवे सुरक्षा आयुक्त (सीसीआरएस) की निगरानी में गुरुवार को हुए इस परीक्षण में ट्रेन की तेज गति पर प्रदर्शन क्षमता, परिचालन दक्षता और

सुरक्षा मानकों का आकलन किया गया। रेल मंत्रालय के अनुसार, परीक्षण की सफलता आधुनिक वंदे भारत ट्रेनसेट के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इससे देश में आधुनिक रेलगाड़ियों के निर्माण और उन्नत रेल तकनीक के क्षेत्र में विकास हो रही क्षमताओं को भी रेखांकित किया गया है। कपूरथला रेल कोच फैक्टरी में निर्मित इस वंदे भारत ट्रेन में 16 डिब्बे हैं और यह उन्नत प्रणोदन



प्रणाली से लेस है। परीक्षण के दौरान ट्रेन के उच्च गति पर प्रदर्शन और निर्धारित

सुरक्षा मानकों का मूल्यांकन किया गया। हालांकि,परीक्षण सफल होने का अर्थ अपने आप में इस ट्रेनसेट को नियमित यात्री सेवा के लिए मंजूरी मिलना नहीं है। आरसीएफ कपूरथला आधुनिक रेल डिब्बों के निर्माण का प्रमुख केंद्र है। यहां वंदे भारत और अमृत भारत जैसी आधुनिक रेलगाड़ियों के लिए डिब्बे तैयार किए जाते हैं। फैक्टरी की विनिर्माण क्षमता ने भारतीय रेलवे के आधुनिक रेल बेड़े के विस्तार में

योगदान दिया है। रेल कोच फैक्टरी ने वित्त वर्ष 2025-26 में कुल 2,383 डिब्बों का उत्पादन किया, जो उसके इतिहास में अब तक का सर्वाधिक वार्षिक उत्पादन है। यह उपलब्धि फैक्टरी की उत्पादन क्षमता और आधुनिक रेल डिब्बों की बढ़ती विनिर्माण गतिविधियों को दर्शाती है। आरसीएफ में निर्मित रेल डिब्बों का एशिया और अफ्रीका के विभिन्न देशों में निर्यात भी किया गया है।

संपादकीय

संस्थाओं की साख पर निशाना

उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों की औपचारिक घोषणा में अभी देर है, लेकिन सियासी मोर्चेबंदी तेज होती जा रही है। विपक्षी दलों के मोर्चे आईएनडीआर को लगता है कि जिस तरह बीते लोकसभा चुनावों में 'संविधान रक्षा' का उसका दांव किंचित सफल रहा था,उसकी तुलना में एसआईआर का विरोध उसके लिए कहीं ज्यादा कारगर साबित हो सकता है। एसआईआर और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ उसका धरना-प्रदर्शन उसके इसी सोच का प्रतीक है। विपक्षी गठबंधन को लगता है कि एसआईआर उसके लिए ऐसा सियासी हथियार साबित होगा,जिसके जरिये वह भाजपा को हरा सकता है। विपक्षी गठबंधन का यह मंसूबा कितना सफल होगा, यह बाद में पता चलेगा, लेकिन एसआईआर के बहाने विपक्ष जो राजनीतिक उठापटक कर रहा है, उसकी असंलिखित को जानना-समझना जरूरी हो जाता है।

यह पहला मौका नहीं है जब चुनाव में पराजित राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाया हो। 1971 के आम चुनाव में हार के बाद भारतीय जनसंघ के प्रमुख बलराज मधोक ने रूसी स्याही के जरिये चुनावी फर्जीवाड़े का आरोप लगाया था। हालांकि पहले राजनीतिक दल कम से कम इस तथ्य का ध्यान रखते थे कि संस्था के रूप में चुनाव आयोग की साख कमजोर न हो। केंद्र में नरेन्द्र मोदी के उभार के बाद करीब हर चुनाव में हार रहे दल चुनाव आयोग पर सवाल तो उठा ही रहे हैं, साथ ही उसकी साख पर भी आघात कर रहे हैं। 2014 की चुनावी हार के समय विपक्षी दल सकते में रहे, इसलिए तब चुनाव आयोग के खिलाफ सवाल नहीं उठे। अलबत्ता इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों यानी ईवीएम को हैक करने का शिगूफा छेड़ा जाने लगा।

इसे कांग्रेस की अगुआई में लगभग समूचे विपक्षी दलों ने हवा दी। विपक्षी दलों के इस कोरस गान में वामपंथी वैचारिकी ने भरपूर सहयोग दिया। ईवीएम को हैक करने को लेकर हास्यास्पद दावे तक किए गए। हारकर चुनाव आयोग को ईवीएम हैक करने के लिए सार्वजनिक चुनौती देनी पड़ी,जिसका किसी के पास कोई जवाब नहीं था। फिर भी एक के बाद एक चुनावों में भाजपा की जीत पर ईवीएम को घेरा जाता रहा। हालांकि जब 2015 के बिहार, 2020 के दिल्ली, 2016 और 2021 के बंगाल विधानसभा चुनावों में भाजपा तमाम कोशिशों के बावजूद हार गई, तब कोई हंगामा नहीं हुआ।

आज देश की राजनीति जिस पड़व पर है,उसमें विरोधियों की साख को हवा में उछलाना बड़ा कार्य मान लिया गया है। जैसे अगर किसी चुनाव में भाजपा को जीत मिलती है तो विपक्षियों का तर्क होता है कि चुनाव आयोग ने ईवीएम में हेराफेरी करके उसे जिता दिया। वहीं भाजपा जब हार जाती है तो यही विपक्षी खेमा जीत का जश्न मनाते हुए कहता है कि भाजपा जानबूझकर चुनाव हार गई। बंगाल में भाजपा की जीत विपक्ष को पच नहीं रही, लेकिन केरल और तमिलनाडु में अपनी जीत में उसे कोई खराबी नहीं दिखती। वास्तविकता यह है कि विपक्षी खेमा हार के पीछे अपनी नीतियों की नाकामी और अपने अनाचार को जिम्मेदार नहीं मानता। उल्टे चुनाव आयोग और ईवीएम पर ही टीकरा फोड़ता रहता है।

राहुल गांधी के नेतृत्व वाले विपक्षी खेमे की नजर में मोदी तानाशाह हैं, लेकिन उन्हीं को संसद से लेकर सड़क तक अपशब्दों से भी नवाजने से ये दल नहीं चुकते। जुलाई में जंतर-मंतर पर हुए कारोचर जनता पार्टी के प्रदर्शनों के दौरान मोदी के लिए जिन अश्लील अपशब्दों की जो बाँछार हुई,विपक्षी खेमा उन पर लहलहाते नजर आया। सवाल यह है कि ऐसा कौन-सा तानाशाह होगा,जिसे ऐसी गालियां खुलेआम दी जा सकती हैं? और वह गालीबाजों को दंडित करने के बजाय उन्हें क्षमा कर दे। जहां तक ज्ञानेश कुमार की बात है तो वह उसी केरल कैडर के आईएएस अधिकारी रहे हैं, जहां समय-समय पर कांग्रेस-वाम दलों की सरकारें रही हैं। जाहिर है कि राज्य में काम करते वक्त उनका रिश्ता वामपंथी और कांग्रेसी नेताओं से भी रहा होगा। दोनों भले ही राज्य में विरोधी हों, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में दोनों खेमों के साझा एरुमन मोदी और भाजपा हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि गृह मंत्रालय में सेवा के दौरान अनुच्छेद 370 की समीति में ज्ञानेश कुमार की भूमिका और समान नागरिक संहिता के लिए जमीन तैयार करने जैसे कार्यों के चलते भी वे विपक्षी दलों की आंखों की रिकंरिकी बन चुके हैं।

यह पहला मौका नहीं है जब किसी लोकतांत्रिक संस्था को साखहीन साबित करने के लिए विपक्षी खेमे ने अपने घोड़े नहीं खोले। मोदी के सत्ता में आने के साढ़े तीन साल बाद न्यायपालिका को उनकी सरकार के इशारों पर नाचने वाला बताने की कोशिशें खूब हुईं। सीबीआई से लेकर इंडी की कारवाइयों की ही राजनीति से प्रेरित बताया जाता। चाहे ऐसी कार्रवाई खुंखार अपराधियों,आतंकियों और जालसाजों के खिलाफ क्यों न हो। किसी अल्पसंख्यक अपराधी के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई कर दी, तो उसे सांप्रदायिक नजरिये से देखने और दिखाने का प्रपंच किया जाता। यहां तक कि विपक्षी दल जून 2020 में गलवन घाटी में भारतीय और चीनी सेना के बीच संघर्ष में भी भारतीय सैन्य बलों को कमजोर दिखाने से बाज नहीं आए। जबकि तमाम अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के अनुसार गलवन में भारतीय सैनिकों का पलड़ा ही भारी रहा था।

आज यह स्पष्ट है कि विपक्ष का अभियान जन के मन में पैठ नहीं कर पा रहा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने वोटर अक्विरा यात्रा निकाली थी, जो टांग-टांग फिस्स साबित हुई। इसके पहले जनवरी, 2024 में मणिपुर से शुरू और मुंबई में खत्म हुई 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' में मोदी के निशाने पर होना कोई बड़ी बात नहीं थी,लेकिन इसके जरिये सीधे-सीधे संस्थाओं को निशाना बनाने की कोशिश हुई। इस तक जवाबदेही की बात है तो चाहे ज्ञानेश कुमार हों या फिर कोई और, अगर किसी ने गड़बड़ी की है तो उस पर विधिस्मत्त कार्रवाई होनी ही चाहिए।लेकिन संस्थाओं की साख पर सवाल उठाकर ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर संस्थाएं अपनी नैतिक आभा के साथ नहीं बची रही तो तय मानिए कि यह लोकतंत्र की सैहत के लिए शुभ नहीं होगा।



विजय गर्ग

दशकों से डेंगू की रोकथाम मुख्य रूप से मच्छरों को नियंत्रित करने और मच्छर के काटने से बचने पर निर्भर रही है। ऐसे में डेंगू वैक्सीन का विकास और इसकी नियामक स्वीकृति विज्ञान की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि और नया मोड़ है। डेंगू डेंगू वायरस के कारण होता है, जिसके चार प्रमुख सीरोटाइप डीईएनवी-1, डीईएनवी-2, डीईएनवी-3 और डीईएनवी-4-माने जाते हैं। किसी व्यक्ति को एक से अधिक बार डेंगू हो सकता है, क्योंकि एक सीरोटाइप से प्राप्त प्रतिरक्षा दूसरे सीरोटाइप से पूर्ण सुरक्षा प्रदान नहीं करती। इस जैविक जटिलता ने सुरक्षित और प्रभावी डेंगू वैक्सीन विकसित करना वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी चुनौती बना दिया है।

डेंगू की शुरुआती वैक्सीनों को नियामक स्वीकृति मिलना इस बात का प्रमाण था कि डेंगू के विरुद्ध टीकाकरण वैज्ञानिक रूप से संभव है। हालांकि, डेंगू का टीकाकरण कई अन्य संक्रामक रोगों के टीकाकरण जितना सरल नहीं है। वैक्सीन की प्रभावशीलता व्यक्ति की आयु, पहले डेंगू संक्रमण हुआ है या नहीं, वायरस के प्रचलित सीरोटाइप और इस्तेमाल में जा रही वैक्सीन के आधार पर अलग-अलग हो सकती है। इसलिए टीकाकरण संबंधी

डेंगू दुनिया के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में फैलने वाली प्रमुख मच्छर-जनित बीमारियों में से एक बन चुका है...हर वर्ष इसके प्रकोप से परिवारों,अस्पतालों और सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था पर भारी दबाव पड़ता है...तेज बुखार,सिरदर्द, शरीर में दर्द,कमजोरी और कुछ मामलों में रक्तस्राव या शॉक जैसी गंभीर स्थितियां डेंगू को खतरनाक बना सकती हैं...

नीतियां वैज्ञानिक प्रमाणों और संबंधित स्वास्थ्य अधिकारियों की सिफारिशों पर आधारित होनी चाहिए। डेंगू वैक्सीन अनुसंधान से मिली एक महत्वपूर्ण सीख पहले हो चुके डेंगू संक्रमण की भूमिका है। कुछ वैक्सीनों ने पहले डेंगू से संक्रमित हो चुके लोगों और कभी संक्रमित न हुए लोगों में अलग-अलग लाभ और जोखिम दिखाए हैं। इसलिए कुछ वैक्सीनों के मामले में टीकाकरण से पहले उचित मूल्यांकन और पात्र लोगों का सावधानीपूर्वक चयन विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है।

आधुनिक डेंगू वैक्सीन का उद्देश्य शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को इस प्रकार प्रशिक्षित करना है कि वह वायरस से पहले पहचानकर उससे लड़ सके। प्रतिरक्षा स्मृति को सक्रिय करके टीकाकरण लक्षणयुक्त डेंगू के जोखिम को कम कर सकता है और वैक्सीन तथा संबंधित आबादी के आधार पर गंभीर बीमारी और अस्पताल में भर्ती होने की संभावना को भी कम कर सकता है।

हालांकि, वैक्सीन लगवाने के बाद पूर्ण सुरक्षा की गलत धारणा नहीं बननी चाहिए। डेंगू मुख्य रूप से एडीज मच्छरों, विशेषकर एडीज एजिटी , के माध्यम से फैलता है। ये मच्छर घरों, स्कूलों, निर्माण स्थलों और आसपास जमा थोड़े से पानी में भी पनप सकते हैं। जमा पानी को प्रतिचलित सीरोटाइप और इस्तेमाल का प्रयोग करना, शरीर को ढकने वाले कपड़े पहनना, छिड़कियों पर जाली लगाना और



आसपास स्वच्छता बनाए रखना आज भी अत्यंत आवश्यक उपाय हैं।

डेंगू वैक्सीन का आगमन जिम्मेदार सार्वजनिक स्वास्थ्य संचार के महत्व को भी उजागर करता है। लोगों को स्पष्ट जानकारी मिलनी चाहिए कि कौन सा टीका लगवा सकता है, कितनी खुराकों की आवश्यकता है, संभावित दुष्प्रभाव क्या हो सकते हैं और वैक्सीन से कितनी सुरक्षा की अपेक्षा की जा सकती है। टीकाकरण संबंधी निर्णय सोशल मीडिया की अफवाहों के बजाय स्वास्थ्य अधिकारियों और योग्य चिकित्सकीय विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार किए जाने चाहिए।

भारत जैसे देशों में डेंगू की रोकथाम विशेष रूप से महत्वपूर्ण है,क्योंकि इसके प्रकोप विभिन्न क्षेत्रों में दिखाई दे सकते हैं और जलवायु,वर्षा,शहरीकरण तथा

मच्छरों की संख्या के अनुसार इसके प्रसार का स्वरूप बदल सकता है। बढ़ता तापमान और बदलता वर्षा-चक्र भी मच्छर-जनित बीमारियों के भौगोलिक और मौसमी प्रसार को प्रभावित कर सकता है।

डेंगू टीकाकरण के क्षेत्र में प्रगति के साथ-साथ निदान, निगरानी,मच्छर नियंत्रण और उपचार के क्षेत्रों में भी वैज्ञानिक प्रगति हुई है। शोधकर्ता नई वैक्सीन तकनीकों और डेंगू वायरस के सभी प्रमुख सीरोटाइपों के विरुद्ध बेहतर सुरक्षा के तरीकों का अध्ययन कर रहे हैं। अंतिम उद्देश्य केवल वैक्सीन विकसित करना नहीं,बल्कि ऐसी व्यापक रणनीति तैयार करना है जो बीमारी, मृत्यु और डेंगू के सामाजिक तथा आर्थिक बोझ को कम कर सके।

डेंगू वैक्सीन का विकास यह दर्शाता है

कि कठिन सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान निरंतर वैज्ञानिक अनुसंधान से संभव है। वर्षों के प्रयोगशाला अध्ययनों, क्लिनिकल परीक्षणों, प्रतिरक्षा विज्ञान और महामारी विज्ञान से संबंधित शोध ने इस प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

फिर भी डेंगू के विरुद्ध लड़ाई केवल वैक्सीन से नहीं जीती जा सकती। सरकारों,स्वास्थ्य विशेषज्ञों, स्कूलों,समुदायों और प्रत्येक व्यक्ति की इसमें भूमिका है। चेतावनी संकेतों की समय पर पहचान,शीघ्र चिकित्सकीय सहायता,मच्छर नियंत्रण और वैज्ञानिक प्रमाणों पर आधारित टीकाकरण नीतियां-इन सभी उपायों को साथ लेकर चलना आवश्यक है।

इसलिए डेंगू के विरुद्ध टीकाकरण केवल एक चिकित्सकीय उपलब्धि नहीं है,बल्कि मच्छर-जनित बीमारियों के खिलाफ चल रही लंबी लड़ाई का एक नया अध्याय है। विज्ञान ने हमें एक और महत्वपूर्ण साधन दिया है;अब चुनौती इस साधन का सुरक्षित,विवेकपूर्ण और समान रूप से उपयोग करने की है।

संदेश स्पष्ट है-टीकाकरण डेंगू के विरुद्ध हमारी सुरक्षा को मजबूत कर सकता है,लेकिन रोकथाम हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। वैज्ञानिक नवाचार,जिम्मेदार टीकाकरण,मच्छर नियंत्रण और जन-जागरूकता का संयोजन हमें ऐसे भविष्य के करीब ले जा सकता है, जहां डेंगू के कारण होने वाली पीड़ा काफी कम हो।

नारी सशक्तिकरण का पर्व है नवरात्रि

को मानते हुए इस देश में भाईचारे की भावना के साथ सदियों से एक साथ रहते चले आ रहे हैं। यही कारण है की पूरे विश्व में भारत की धर्म व संस्कृति सर्वोत्तम माना गयी है। विभिन्न धर्मों के साथ जुड़े कई पर्व भी है जिसे भारत के कोने-कोने में श्रद्धा,भक्ति और धूमधाम से मनाया जाता है। उन्ही में से एक है नवरात्रि। वस्तन्त की शुरुआत और शरद ऋतु की शुरुआत, जलवायु और सूरज के प्रभावों का महत्वपूर्ण संगम माना जाता है। इन दो समय मां दुर्गा की पूजा के लिए पवित्र अवसर माने जाते है। त्योहार की तिथियां चन्द्र कैलेंडर के अनुसार निर्धारित होती हैं। यह पूजा वैदिक युग से पहले प्रागैतिहासिक काल से है। नवरात्रि के पहले तीन दिन देवी दुर्गा की पूजा करने के लिए समर्पित है। आठवे दिन पर एक यज्ञ किया जाता है। नौवा दिन नवरात्रि समारोह का अंतिम दिन है। यह महानवमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन उन नौ जवान लड़कियों की पूजा होती है जो अभी तक यौवन की अवस्था तक नहीं पहुंची है। इन नौ लड़कियों को देवी दुर्गा के नौ रूपों का प्रतीक माना जाता है। लड़कियों का सम्मान तथा स्वागत करने के लिए उनके घर धौए जाते हैं। पूजा के अंत में लड़कियों को उपहार के रूप में नए कपड़े, वस्तुयें, फल प्रदान किए जाते है।

नवरात्रि वर्ष में चार बार आता है। चैत्र,आषाढ़, अश्विन, पौष प्रतिपदा से नवमी तक मनाया जाता है। नवरात्रि के नौ रातों में तीन देखियों महालक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा होती है जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। दुर्गा का मतलब जीवन के दुख को हटानेवाली होता है। नवरात्रि एक महत्वपूर्ण प्रमुख त्योहार है जिसे पूरे भारत में पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। नवरात्रि का त्योहार असत्य पर सत्य की जीत को दर्शाता है। हिन्दू मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि साल में दो बार मनाया जाता है। हिंदी महीनो के मुताबिक पहला नवरात्रि चैत्र महीने में मनाया जाता है और दूसरी बार अश्विन महीने में मनाया जाता है। नवरात्रि नि द्दिनों तक निरंतर चलता है जिसमे देवी माँ के अलग अलग स्वरूपों की लोग भक्ति और निष्ठा के साथ पूजा करते है। भारत में नवरात्रि अलग



अलग राज्यों में विभिन्न तरीकों और विधियों के संग मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन्हीं नौ दिनों में मां दुर्गा धरती पर आती है। उनके आने की खुशी में इन दिनों को दुर्गा उत्सव के तौर पर

देशभर में धूमधाम से मनाया जाता है।

नवरात्रि के पहले दिन बालिकाओं की पूजा की जाती है। दूसरे दिन युवती की पूजा की जाती है। तीसरे दिन जो महिला परित्रुक्ता के चरण में पहुंच गयी है, उसकि पूजा की जाती है। नवरात्रि के चैथे, पांचवें और छठे दिन लक्ष्मी- समृद्धि और शांति की देवी की पूजा करने के लिए समर्पित है। आठवे दिन पर एक यज्ञ किया जाता है। नौवा दिन नवरात्रि समारोह का अंतिम दिन है। यह महानवमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन उन नौ जवान लड़कियों की पूजा होती है जो अभी तक यौवन की अवस्था तक नहीं पहुंची है। इन नौ लड़कियों को देवी दुर्गा के नौ रूपों का प्रतीक माना जाता है। लड़कियों का सम्मान तथा स्वागत करने के लिए उनके घर धौए जाते हैं। पूजा के अंत में लड़कियों को उपहार के रूप में नए कपड़े, वस्तुयें, फल प्रदान किए जाते है।

शक्ति की उपासना का पर्व शारदीय नवरात्र प्रतिपदा से नवमी तक निश्चित नौ तिथि,नौ नक्षत्र,नौ शक्तियों की नवधा भक्ति के साथ सनातन काल से मनाया जा रहा है। आदिशक्ति के हर रूप की नवरात्र के नौ दिनों में क्रमशरू अलग-अलग पूजा की जाती है। मां दुर्गा की नौवीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियां देने वाली हैं। इनका वाहन सिंह है और कमल पुष्प पर ही आसीन होती हैं। नवरात्रि के नौवें दिन इनकी उपासना की जाती है।

इस पर्व से जुड़ी एक कथा अनुसार देवी दुर्गा ने एक भैंस रूपी असुर अर्थात महिषासुर का वध किया था।

सर्बिया से नेपाल: एक जैसी पटकथा के बाद अब निशाने पर भारत

संजय सक्सेना,लखनऊ, उत्तरप्रदेश

भारत में आज जिस तरह से काँकरोच जनता पार्टी, वामपंथी और इंडी गठबंधन कथित रूप से चुनाव में धांधली को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ लामबंद हैं, ऐसा कई देशों में पहले भी हो चुका है। दरअसल, यह सब सुनिश्चित होता है,जिसके पीछे अवसर कई बड़े देशों की सरकारों से लेकर अपने हित साधने में लगे विदेशी उद्योगपति तक शामिल होते हैं। अपनी कोशिशों का अंजाम देने के लिए ये ताकतें हर देश में हालात ऐसे बना देती हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारों को इस्तीफा देना या सत्ता छोड़कर भागना तक पड़ जाता है। वर्तमान वैश्विक भू-राजनीति में किसी भी देश को अस्थिर करने या वहाँ अपनी पसंद की सरकार स्थापित करने के लिए सीधे सैन्य आक्रमण के बजाय एक नया और बेहद खतरनाक हथियार अपनाया जा रहा है, जिसे राजनीतिक विश्लेषक हार्ब्रिड वॉरफैयर या क्लर रेवोल्यूशन ('रंगीन क्रांतियाँ') कहते हैं। इस रणनीति का सबसे पहला और बुनियादी कदम होता है, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार की वैधता को समाप्त करने के लिए कभी शिक्षा में खामियाँ बताकर तो कभी चुनावी धांधली का एक सुनिश्चित नैरेटिव गढ़ा जाता है। भारत जैसे परिपक्व लोकतंत्र में ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) और चुनावी प्रक्रिया पर समय-समय पर उठाए जाने वाले सवाल इसी वैश्विक ट्रूलकिट का हिस्सा माने जाते हैं। लेकिन भारत से पहले, यह खेल दुनिया के कई देशों में सफलतापूर्वक खेला जा चुका है, जहाँ इसके चलते बड़े पैमाने पर अराजकता फैली और चुनी हुई सरकारों

उखाड़ फेंकी गईं।इस पूरी प्रक्रिया,इसके पीछे काम करने वाली ताकतों,फंडाई के स्रोतों और प्रभावित देशों का एक विस्तृत व गहन विश्लेषण किया जाए, तो पता चलता है कि भारत से पहले भी कई देशों में ऐसा नैरेटिव गढ़ा जा चुका है। इतिहास गवाह है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद,विशेष रूप से पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया में,इस फॉर्मूले का बार-बार इस्तेमाल किया गया। वर्ष 2000 में सर्बिया में बुलडोजर रेवोल्यूशन में राष्ट्रपति स्लोबोदान मिलोसेविच के खिलाफ विपक्ष ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। बड़े पैमाने पर जनआंदोलन खड़ा किया गया और मिलोसेविच को सत्ता छोड़नी पड़ी। 2003 में जॉर्जिया में रोज रेवोल्यूशन (गुलाबी क्रांति) के द्वारा संसदीय चुनावों में धांधली के आरोपों को हवा दी गई। जनता को सड़कों पर उतारा गया और राष्ट्रपति एडुआर्ड शेवार्डनादज़े को इस्तीफा देने पर मजबूर किया गया। 2004 में यूक्रेन में ऑरेंज रेवोल्यूशन (नारंगी क्रांति) के द्वारा राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों को धांधली बताकर खारिज कर दिया गया।

सूचना

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटीक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को उस पहुँचाना। सभी विवादों का निपटारा अंभिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।

सम्पादक

लोकतंत्र की असली खूबसूरती कुर्सी की सुरक्षा में नहीं,बल्कि अंतिम व्यक्ति की मुस्कान में निहित है...

डॉ.मुश्ताक अहमद शाह सहज,हरादा,मध्य प्रदेश

देश के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य पर नज़र डालें तो एक बेहद विडंबनापूर्ण और चिंताजनक तस्वीर उभरती है। संसद से लेकर सड़क तक,सत्ता के गलियारों में केवल एक ही धुरी पर सियासत घूम रही है कुर्सी,जी हाँ कुर्सी की चाहत,एक तरफ़ सत्तासीन दल अपनी विजय और वर्चस्व को बनाए रखने की जद्दोजहद में है; तो दूसरी तरफ़ विपक्ष हर उस मौके की तलाश में है जिससे सत्ता की सीढ़ियाँ उसके हाथ लग सकें। इस रस्साकशी के केंद्र में अगर कोई सबसे ज्यादा पिस रहा है, तो वह है देश की बेचारी जनता, जिसकी आँखें लोकतंत्र के इस खेल में केवल तमाशाबीन बनकर रह गई हैं।

खाली हाथ जनता और मताधिकार की मजबूरी
 लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व यानी चुनाव, जनता के लिए अब उन्मीद से ज्यादा एक विवशता (मजबूरी) बनता जा रहा है। मतदान के दिन कतारों में खड़ी जनता के हाथ में भले ही लोकतंत्र की खरबों बड़ी ताकत यानी वोट की ताकत होती है, लेकिन परिणाम आने के बाद वही जनता खुद को ठगा और खाली हाथ महसूस करती है। रोजगार की तलाश में दर-दर भटकते युवा, महंगाई की मार से कराहता मध्यम और गरीब वर्ग, जब यह देखता है कि चुनाव के समय

किए गए वादे हवा हो गए, तो उसका लोकतंत्र से भरोसा डामगाने लगता है। आज़ादी के इतने दशकों बाद भी आम आदमी की बुनियादी जरूरतें (रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार) चुनावी बहसों के केंद्र से गु़ावब होकर केवल घोषणापत्रों के पत्रों तक सिमट कर रह गई हैं।

सुलतान जनाक्रोश और राजनीतिक बहरापन,

देश के भीतर आज जो असंतोष सुलग रहा है, वह किसी से छिपा नहीं है। जब एक पढ़ा-लिखा युवा नौकरी के लिए लाठी खाने को मजबूर होता है, जब गृहिणियां बढ़ती रसोई गैस और खाद्य पदार्थों की क़ीमतों के आगे दम तोड़ती हैं, तो समाज में एक जनाक्रोश जन्म लेता है।

लेकिन विडंबना यह है कि सत्ता और विपक्ष दोनों ही इस जन-आक्रोश की भाषा को या तो सुनना नहीं चाहते या फिर इसे अपनी सुविधानुसार राजनीतिक चश्मे से देखते हैं। जनता की तकलीफें जब चुनावी एजेंडे से बाहर हो जाती हैं, तब यह आक्रोश व्यवस्था के प्रति अविश्वास में बदलने लगता है, जो किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ख़तरनाक संकेत है।

पक्ष और विपक्ष की सहमती का अभाव क्यों?

सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि मंहगाई,



रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर देश के सभी राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति क्यों नहीं बन पाती?

राजनीतिक नफा-नुकसान हमारे यहाँ की राजनीति सहयोग पर नहीं, बल्कि विरोध की संस्कृति पर टिकी है। यदि एक दल किसी गंभीर मुद्दे पर सुधार की बात करता है, तो दूसरा दल उसमें अपनी राजनीतिक ज़मीन तलाशने लगता है।

चुनावी चश्मे से नीतियां,और योजनाएं,
 हर मुद्दे को दीर्घकालिक राष्ट्रीय विकास के दृष्टिकोण से देखने के बजाय अगले

नाइस क्लब बलसेड़ी ने 2-1 से व केपीसी धौरपुर की टीम ने ट्राई ब्रेकर में दर्ज की जीत



—संवाददाता—

अम्बिकापुर,09 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)।

नगर के गांधी स्टेडियम में खेली जा रही संभाग स्तरीय नॉकआउट कम लीग फुटबॉल प्रतियोगिता में शुक्रवार को दो मुकाबले खेले गए। पहले मैच में नाइस क्लब बलसेड़ी ने शानदार वापसी करते हुए खुडियारानी मनोहरपुर को 2-1 से हराया। वहीं, दूसरे मुकाबले में केपीसी धौरपुर ने किसान क्लब को ट्राईब्रेकर में 5-4 से शिकस्त दी। पहले मुकाबले में खुडियारानी मनोहरपुर की टीम ने बेहतर तालमेल के साथ खेलते हुए पहले हाफ में 1-0 की बढ़त बना ली। दूसरे हाफ में नाइस क्लब बलसेड़ी ने आक्रामक खेल दिखाया। टीम ने अंतिम समय में लगातार दो गोल दागकर मुकाबले का रुख पलट दिया और 2-1 से जीत दर्ज की। दूसरा मुकाबला किसान क्लब और केपीसी धौरपुर के बीच खेला गया। दोनों टीमों ने शुरुआत से ही गोल करने के प्रयास किए, लेकिन निर्धारित समय तक कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी। दोनों हाफ में खिताडियों ने एक-दूसरे पर दबाव बनाए रखा। अंततः मैच का फैसला ट्राईब्रेकर से हुआ, जिसमें केपीसी धौरपुर ने 5-4 से जीत हासिल की। प्रतियोगिता में शनिवार को पहला मुकाबला पीजी रॉयल अंबिकापुर और एफसी कंचनपुर के बीच खेला जाएगा। दूसरे मैच में डी ब्रदर्स बटनीझरिया का सामना कोलटस क्लब देवनार से होगा।

पीजी कॉलेज अम्बिकापुर में नुक्कड़ नाटक प्रतियोगिता का आयोजन

—संवाददाता—

अम्बिकापुर,09 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)।

सेवा संकल्प अभियान-2026 के अंतर्गत राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बिकापुर में नुक्कड़ नाटक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का विषय 'विकसित भारत अभियान की परिकल्पना, सेवा एवं राष्ट्र भावना तथा सामाजिक सुधार' रखा गया था। इस अवसर पर महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए अपनी रचनात्मक एवं प्रभावशाली प्रस्तुतियों के माध्यम से समाज में जनजागरूकता का संदेश दिया। प्रतियोगिता में गंगा गुप्त, यमुना गुप्त एवं युथ एक्शन क्लब गुप्त के विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रतिभागियों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका, समाज के प्रति सेवा भावना, राष्ट्रप्रेम, सामाजिक जिम्मेदारी एवं सकारात्मक बदलाव जैसे महत्वपूर्ण विषयों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। विद्यार्थियों की प्रस्तुतियों में सामाजिक कुरीतियों के प्रति जागरूकता, नागरिक कर्तव्यों के निर्वहन तथा राष्ट्र निर्माण में सामूहिक सहभागिता का संदेश प्रमुखता से उभरकर सामने आया।



कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने अपनी अभिनय कला, संवाद शैली एवं रचनात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से सेवा और समर्पण के महत्व को रेखांकित किया। प्रस्तुतियों के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि विकसित भारत के निर्माण में प्रत्येक नागरिक की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए युवाओं को शिक्षा के साथ-साथ सामाजिक सरोकारों, सेवा कार्यों एवं राष्ट्रप्रेम की गतिविधियों में भी आगे आना चाहिए।

शराब पीकर वाहन चलाना पड़ा महंगा, तीन चालकों पर 30 हजार का जुर्माना

—संवाददाता—

अम्बिकापुर,09 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)।

शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ यातायात पुलिस की कार्रवाई में तीन चालक पकड़े गए। इनमें दो मोटरसाइकिल चालक और एक कार चालक शामिल हैं। ब्रेथ एनालाइजर से जांच में तीनों के शराब के नशे में वाहन चलाने की पुष्टि होने पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने तीनों वाहन चालकों पर 10-10 हजार रुपए, कुल 30 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया। यातायात पुलिस के अनुसार, सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए वाहन जांच के दौरान यह कार्रवाई की गई। पहले मामले में मोटरसाइकिल क्रमांक सीजी 15 ईबी 1304 के चालक संतोष कुशवाहा (27), निवासी जमाला, थाना लखनपुर को जांच के लिए रोका गया। ब्रेथ एनालाइजर से जांच में उसके शराब के नशे में वाहन चलाने की पुष्टि हुई। दूसरे मामले में कार क्रमांक सीजी 15 बी 6744 के चालक चिरंजीवी चक्रवर्ती (32), निवासी नर्मदापारा, थाना गांधीनगर को पकड़ा गया। जांच में उसके भी शराब पीकर वाहन चलाने की पुष्टि हुई। वहीं, तीसरे मामले में मोटरसाइकिल क्रमांक सीजी 15 ईएफ 9996 के चालक दिनेश कुमार सिंह (28), निवासी थाना लखनपुर क्षेत्र को जांच के दौरान नशे में वाहन चलते पाया गया। तीनों मामलों में यातायात पुलिस ने धारा 185 मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई कर प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किए।

टीबी मुक्त भारत की मुहिम को मिलेगी युवाओं की ताकत, घर-घर पहुंचेगी 'जोश' टीम बतौली को वर्ष 2025 के लिए टीबी मुक्त विकासखंड का सम्मान, मरीजों की जांच, उपचार और पोषण सहायता पर रहेगा जोर

—संवाददाता—

अम्बिकापुर,09 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)।

टीबी मुक्त भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अब जनभागीदारी और युवा शक्ति पर जोर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में सरगुजा जिले में 'जोश' (ज्वाइंट स्क्वाड फॉर हेल्थ) टीम की शुरुआत की गई है। माई भारत के स्वयंसेवक और एनसीसी कैडेट घर-घर पहुंचकर लोगों को टीबी के लक्षणों, निःशुल्क जांच, उपचार और पोषण सहायता की जानकारी देंगे। वहीं, सरगुजा के बतौली विकासखंड को वर्ष 2025 के लिए टीबी मुक्त विकासखंड का सम्मान मिलने से जिले के प्रयासों को नई पहचान मिली है।

अभियान के तहत टीबी मरीजों को समय पर उपचार दिलाने, सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने और बीमारी को लेकर सामाजिक भेदभाव दूर करने पर विशेष जोर रहेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने 8 अक्टूबर को नई दिल्ली के भारत मंडप में राष्ट्रीय स्तर पर जोश टीम का शुभारंभ किया। प्रथम चरण में देश के 11 राज्यों के 55 जिलों में यह पहल शुरू की गई है। इसी



क्रम में कलेक्टर अजीत बसंत के मार्गदर्शन में सरगुजा में भी टीम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में टीबी उन्मूलन की निगरानी के लिए नियुक्त अधिकारी, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि, सरपंच, पंच, स्वास्थ्य अधिकारी और युवा स्वयंसेवक शामिल हुए।

स्वयंसेवक बनेंगे जागरूकता अभियान की कड़ी : जोश टीम में माई भारत के स्वयंसेवकों और एनसीसी कैडेट को शामिल किया गया है। कार्यक्रम में माई भारत के जिला नोडल अधिकारी प्रिंस सहित विभिन्न विकासखंडों में कार्यरत

स्वयंसेवकों को टीबी जागरूकता के लिए विशेष किट प्रदान की गई। ये स्वयंसेवक स्वास्थ्य विभाग और पंचायत प्रतिनिधियों के साथ समन्वय कर लोगों को बीमारी के लक्षण पहचानने, समय पर जांच कराने और उपचार पूरा करने के लिए प्रेरित करेंगे। साथ ही पात्र मरीजों को पोषण सहायता और शासन की योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी।

इससे ग्रामीण क्षेत्रों में टीबी के प्रति जागरूकता बढ़ाने और मरीजों को स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ने में मदद मिलने की उम्मीद है।

परेड में अनुशासन और टर्नआउट की जांच...183 पुलिसकर्मी हुए शामिल

डीआईजी एवं एसएसपी राजेश अग्रवाल ने ली जनरल परेड की सलामी, बेहतर वर्दी और प्रदर्शन करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों को किया पुरस्कृत

—संवाददाता—

अम्बिकापुर,09 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)।

पुलिस की वर्दी, अनुशासन और कार्यशैली ही जनता के बीच उसकी छवि तय करती है। इसी को ध्यान में रखते हुए शुक्रवार को रक्षित केंद्र अंबिकापुर में जनरल परेड का आयोजन किया गया। डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश अग्रवाल ने परेड की सलामी लेने के बाद अधिकारी-कर्मचारियों के टर्नआउट, अनुशासन और परेड प्रदर्शन का निरीक्षण किया। बेहतर टर्नआउट और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पुलिसकर्मियों को पुरस्कृत कर उनका उत्साह बढ़ाया गया। परेड में जिले के कुल 183 अधिकारी-कर्मचारी शामिल हुए। 9 अक्टूबर को आयोजित परेड के दौरान पुलिसकर्मियों को टोलीवार परेड कराई गई। अधिकारियों ने वर्दी और टर्नआउट का निरीक्षण कर पुलिस बल में अनुशासन बनाए रखने पर जोर दिया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, नियमित परेड का उद्देश्य जवानों की शारीरिक फिटनेस, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और अनुशासन को मजबूत करना है।

फरियान और शालीन व्यवहार रखने के निर्देश : डीआईजी एवं एसएसपी राजेश अग्रवाल ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों



को जनता के बीच बेहतर छवि बनाए रखने के लिए अनुशासन का पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने नागरिकों की शिकायतों का त्वरित निराकरण करने तथा थाने पहुंचने वाले फरियानियों के साथ शालीन और संवेदनशील व्यवहार रखने की हिदायत दी। पुलिस की कार्यप्रणाली में व्यवहार और जवाबदेही को महत्वपूर्ण बताते हुए आम लोगों की समस्याओं के प्रति गंभीर रहने पर जोर दिया गया।

पुलिस ब्रिन्ट बैंक के कामकाज पर भी दिए निर्देश : रक्षित केंद्र में जवानों के कल्याण के लिए संचालित पुलिस ब्रिन्ट बैंक के संबंध में भी

आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। अधिकारियों-कर्मचारियों को जरूरत के समय बैंक के माध्यम से मिलने वाली सुविधाओं और लाभों का समय पर उपयोग सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। जनरल परेड में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रितेश चौधरी, नगर पुलिस अधीक्षक राहुल बंसल, उप पुलिस अधीक्षक अमृत कुजूर, अजाक डीएसपी सुरेश भागत, डीएसपी जेपी भारतेन्दु रक्षित निरीक्षक तुषि सिंह राजपूत, कोतवाली थाना प्रभारी सहित प्रशिक्षु सुबेदार, प्रशिक्षु उप निरीक्षक तथा विभिन्न थाना-चौकियों और कार्यालयों के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।

आईपीएस राहुल बंसल बीजापुर भेजे गए, प्रतीक बंसोडे होंगे नए सिटी सीएसपी

—संवाददाता—

अम्बिकापुर,09 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ शासन गृह विभाग ने बड़ा फैसला करते हुए 18 भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों का तबादला आदेश जारी किया है। यह तबादला प्रशासनिक आधार पर तत्काल प्रभाव से किया गया है। इसी क्रम में अंबिकापुर के नगर पुलिस अधीक्षक (सीएसपी) राहुल बंसल को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नक्सल ऑपरेशन जिला-बीजापुर के पद पर पदस्थ किया गया है। राहुल बंसल की जगह 2024 बैच के युवा

आईपीएस प्रतीक बंसोडे को अंबिकापुर का नया सीएसपी बनाया गया है। प्रतीक वर्तमान में प्रशिक्षु के तौर पर जिला-कोर्कर में पदस्थ थे। उन्हें अब नगर पुलिस अधीक्षक अंबिकापुर की जिम्मेदारी दी गई है। गृह विभाग के सचिव हिम शिखर गुप्ता द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि उक्त अधिकारी संबंधित जिले के अधीनस्थ पदस्थ वरिष्ठतम अधिकारी को अपना कार्यभार सौंपकर कार्यमुक्त होंगे। युवा नगर पुलिस अधीक्षक राहुल बंसल का कार्यकाल अंबिकापुर में काफ़ी चर्चित रहा।

स्वयं सहायता समूहों के नाम पर लोन फर्जीवाड़े का आरोप, 40 समूहों की महिलाएं पहुंचीं कलेक्ट्रेट

—संवाददाता—

अम्बिकापुर,09 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)।

जिले के बतौली क्षेत्र में स्वयं सहायता समूहों के नाम पर कथित ऋण फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। पोक्सरी की फरियाद 40 स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं कलेक्ट्रेट पहुंचीं और जनदर्शन में कलेक्टर अजीत वसंत को शिकायत सौंपकर कार्रवाई की मांग की। महिलाओं का आरोप है कि उनकी जानकारी और सहमति के बिना फर्जी हस्ताक्षर कर ऋण निकाला गया। इतना ही नहीं, महतारी वंदन योजना की राशि सहित अन्य रकम भी उनके



बैंक खातों से काट ली गई। महिलाओं ने ग्रामीण बैंक के तत्कालीन प्रबंधक और भुवनेश्वरी सिदार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उन्हें ऋण लेने की जानकारी नहीं थी, लेकिन बाद में बैंक खातों से राशि कटने का पता चला। महिलाओं ने मामले की निष्पक्ष जांच कराकर जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करने और

उनकी राशि वापस दिलाने की मांग की है। मामले में जिला परियोजना प्रबंधक (डीपीएम) सुभाष मिश्रा ने बताया कि इस संबंध में पहले भी शिकायत मिली थी। जांच के बाद संबंधित महिला को निर्लिखित किया गया था। उन्होंने बताया कि करीब 20 लाख रुपए की रिकवरी राशि सामने आई है। इसमें लगभग 10 लाख रुपए की वसूली के लिए कार्रवाई जारी है। शेष राशि की वसूली भी जल्द किए जाने की कही गई है। राजनीतिक या प्रभावशाली लोगों की संलिप्तता के सवाल पर डीपीएम ने कहा कि इस संबंध में कोई स्पष्ट शिकायत या ठोस साक्ष्य सामने नहीं आए हैं।

आदिवासी जमीन विवाद में तारीखों का पेच : 7 अक्टूबर को होनी थी सुनवाई, 29 सितंबर को ही आदेश का दावा वाइफनगर में अपर कलेक्टर के फैसले पर प्रार्थी ने उठाए सवाल...रिश्वत और मिलीभगत के आरोप, निष्पक्ष जांच की मांग

—संवाददाता—

वाइफनगर,09 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)।

आदिवासी भूमि के कथित गलत नक्शा सुधार से शुरू हुआ विवाद अब राजस्व न्यायालय की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के ग्राम रजखेता की जमीन से जुड़े मामले में प्रार्थी पक्ष का आरोप है कि अपर कलेक्टर न्यायालय में प्रकरण 7 अक्टूबर 2026 को आदेश के लिए नियत था, लेकिन आदेश 29 सितंबर 2026 को ही पारित कर मामला नसीबद्ध कर दिया गया। प्रार्थी ने इस घटनाक्रम को संदिग्ध बताते हुए तत्कालीन अपर कलेक्टर आर.एन. पाण्डेय पर प्रभावी सुनवाई का अवसर नहीं देने और कथित आर्थिक लेन-देन के जरिए फैसला प्रभावित करने के आरोप लगाए हैं। आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। संबंधित अधिकारी और जिन व्यक्तियों के पक्ष में आदेश प्रभावित किए जाने का आरोप है, उनका पक्ष भी सामने आना बाकी है। ऐसे में मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने के लिए आदेश की प्रमाणित प्रति, प्रकरण की आदेश-पत्रिका और संबंधित अभिलेखों का परीक्षण महत्वपूर्ण होगा।



2017 के नक्शा सुधार से शुरू हुआ विवाद : मामले की शुरुआत तहसीलदार वाइफनगर के राजस्व प्रकरण क्रमांक 97/अ-6-अ/2016-17 से हुई थी। इसमें 17 अक्टूबर 2017 को नुति सुधार का आदेश पारित किया गया था। प्रकरण से संबंधित आरोप के अनुसार, आदिवासी रामसुन्दर पिता बोधन गोंड की खसरा नंबर 1035 की 0.28 हेक्टेयर भूमि का नक्शा सुधार करते हुए उसे रामस्वरूप पिता रामगुप्त के नाम दर्ज कर दिया गया। प्रभावित पक्ष का आरोप था कि इस प्रक्रिया में उसे न तो समुचित जानकारी दी गई और न ही अपना पक्ष

रखने का अवसर मिला। बाद में मामला अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), वाइफनगर के न्यायालय पहुंचा।

एसडीओ ने 29 सितंबर 2025 को निरस्त किया था आदेश : अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ने 29 सितंबर 2025 को तहसीलदार के वर्ष 2017 के नुति सुधार आदेश को निरस्त कर दिया था। उपलब्ध विवरण के अनुसार, आदेश में नक्शा सुधार की प्रक्रिया और संबंधित राजस्व अभिलेखों पर सवाल उठाए गए थे। विवाद का एक अंश दिवु खसरा नंबर 1035 और खसरा नंबर 1273 के बीच करीब 2.5

किलोमीटर की दूरी बताया गया। सवाल यह था कि एक-दूसरे से दूर स्थित जमीनों के संबंध में नक्शा सुधार का प्रमाण किस आधार पर तैयार किया गया और उसके लिए किन अभिलेखों का इस्तेमाल हुआ। एसडीओ के आदेश का प्रभावित पक्ष को नोटिस और सुनवाई का अवसर दिए जाने के मुद्दे पर भी आपत्ति दर्ज किए जाने की जानकारी सामने आई थी। साथ ही, राजस्व निरीक्षक की भूमिका और कथित अनियमितताओं की जांच का विषय भी उठाया गया था।

जमीन की बिक्री के बाद बढ़ा विवाद : प्रकरण से जुड़े विवरण में यह भी उल्लेख है कि कथित नुति सुधार के बाद संबंधित भूमि सत्यानन्द पाण्डेय पिता सूर्यमंडी पाण्डेय और आकेत जायसवाल पिता अनिल जायसवाल के नाम बेचे जाने की जानकारी सामने आई थी। इसी घटनाक्रम को लेकर भूमि के रिकॉर्ड में बदलाव, उसके आधार और आप में किसी व्यक्ति की गैरकानूनी भूमिका साबित नहीं करती। इसके लिए संबंधित बिक्री विलेख, राजस्व रिकॉर्ड और सक्षम न्यायालय के आदेशों का परीक्षण जरूरी है।

अपर कलेक्टर न्यायालय में पहुंची अपील : एसडीओ के आदेश के खिलाफ अपर कलेक्टर न्यायालय में अपील दायर की गई। प्रकरण क्रमांक 2025099660100127 में 6 अक्टूबर 2025 को यथास्थिति बनाए रखने का अंतिम आदेश पारित किए जाने का उल्लेख है। इसके बाद विभिन्न तारीखों पर पक्षकारों की उपस्थिति, दस्तावेज और तर्क प्रस्तुत किए गए। उपलब्ध कार्यवाही विवरण के अनुसार, 19 अगस्त 2026 को दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने तर्क के लिए समय मांगा था। 16 सितंबर 2026 को लिखित तर्क प्रस्तुत किए जाने और प्रकरण आदेशार्थ रखे जाने की जानकारी दी गई है। अब विवाद इस बात पर केंद्रित है कि जब प्रकरण 7 अक्टूबर 2026 को आदेश के लिए नियत बताया जा रहा है, तो क्या 29 सितंबर को ही अंतिम आदेश पारित कर दिया गया था? यदि ऐसा हुआ, तो आदेश की तारीख, आदेश-पत्रिका में दर्ज कार्यवाही और पक्षकारों को दी गई सूचना की जांच जरूरी है।

रिश्वत और मिलीभगत के आरोप, जांच की मांग : प्रार्थी पक्ष ने तत्कालीन अपर कलेक्टर आर.एन. पाण्डेय पर आरोप लगाया है कि कथित

आर्थिक लेन-देन के आधार पर निर्णय प्रभावित किया गया और सत्यानन्द पाण्डेय तथा आकेत जायसवाल को लाभ पहुंचाया गया। प्रार्थी का यह भी कहना है कि उसे प्रभावी ढंग से सुनवाई का अवसर नहीं मिला। ये गंभीर आरोप हैं, लेकिन उपलब्ध जानकारी के आधार पर इन्हें प्रमाणित तथ्य नहीं माना जा सकता। इनके सत्यापन के लिए आदेश की प्रमाणित प्रति, संबंधित फाइल की नोटशीट, सुनवाई की तारीखों का विवरण और अन्य साक्ष्यों की स्वतंत्र जांच आवश्यक होगी। संबंधित अधिकारी तथा नामित व्यक्तियों का पक्ष सामने आने के बाद ही आरोपों की पूरी तस्वीर स्पष्ट हो सकेगी।

पांच सवाल, जिनके जवाब जरूरी... इस पूरे प्रकरण में अब कुछ बुनियादी सवालों के जवाब जरूरी हैं...
 ■ क्या अंतिम आदेश वास्तव में 29 सितंबर 2026 को पारित हुआ था, जबकि प्रकरण 7 अक्टूबर के लिए नियत था?
 ■ क्या आदेश से पहले दोनों पक्षों को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर मिला?
 ■ एसडीओ द्वारा नक्शा सुधार की प्रक्रिया पर उठाई गई आपत्तियों पर

अपीलीय न्यायालय ने क्या निष्कर्ष निकाला?

■ कथित नुति सुधार के बाद हुए भूमि हस्तांतरण की वैधानिकता की जांच की गई या नहीं?
 ■ रिश्वत और मिलीभगत के आरोपों की जांच के लिए क्या कोई औपचारिक शिकायत या जांच की मांग संबंधित प्राधिकारी के समक्ष रखी गई है?

राजस्व रिकॉर्ड और न्यायिक प्रक्रिया की पारदर्शिता का सवाल

आदिवासी भूमि से जुड़े इस विवाद में केवल स्वामित्व का प्रश्न नहीं है। राजस्व अभिलेखों में सुधार की प्रक्रिया, प्रभावित पक्ष को सुनवाई का अवसर, जमीन के बाद के हस्तांतरण और अपीलीय आदेश की पारदर्शिता भी महत्वपूर्ण हैं। प्रार्थी पक्ष ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। अब आदेश की वास्तविक तारीख, उसकी प्रमाणित प्रति और प्रकरण की संपूर्ण कार्यवाही सामने आने से यह स्पष्ट हो सकेगा कि प्रक्रिया में कोई अनियमितता हुई या नहीं। आरोपों की निष्पक्ष जांच और संबंधित पक्षों का जवाब ही इस विवाद की वास्तविक स्थिति सामने ला सकता है।

सोनहत के दुर्गम वनांचलों में स्वास्थ्य विभाग का विशेष अभियान,चार गांवों में पहुंचे चिकित्सक,214 मरीजों का उपचार

खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. प्रियंका पांडेय के नेतृत्व में गठित तीन चिकित्सा दलों ने संभाला मोर्चा



विशेष दल ने स्कूली बच्चों की जांच कर दी निःशुल्क दवाएं,मलेरिया जांच में नहीं मिला एक भी सक्रिय मामला

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बलवंत सिंह के निर्देश पर जारी है शिविर
-राजन पाण्डेय-

सोनहत/कोरिया,09 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)।

वनांचल और दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बीमारियों की सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग ने जिस तत्परता से गांवों तक पहुंचकर उपचार की व्यवस्था की,उससे ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली है,सोनहत विकासखंड के दुर्गम गांव निमोहर, कचोहर,देवतीडांड और बंसीपुर में स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने एक साथ विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाकर कुल 214 मरीजों की जांच की और उन्हें आवश्यक दवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराईं। दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के बीच गांवों तक चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाने की इस पहल में विभागीय अधिकारियों के निर्देशन से लेकर मैदानी अमले की सक्रियता तक देखने को मिली। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों के अनुरूप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बलवंत सिंह ने मौसमी बीमारियों की रोकथाम और ग्रामीणों को समय पर उपचार उपलब्ध कराने

पर जोर दिया,वहीं,सोनहत की खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. प्रियंका पांडेय ने जमीनी स्तर पर व्यवस्था संभालते हुए तीन अलग-अलग चिकित्सा दल गठित किए,इन दलों में एमबीबीएस और बीएमएस चिकित्सकों के साथ आवश्यक स्वास्थ्यकर्मियों को शामिल किया गया,ताकि एक ही दिन में अलग-अलग दुर्गम गांवों तक पहुंचकर मरीजों की जांच,उपचार और दवा वितरण का कार्य किया जा सके।

चार गांवों में एक साथ स्वास्थ्य शिविर, 214 मरीजों को मिला उपचार-8 अक्टूबर 2026 को आयोजित विशेष स्वास्थ्य शिविरों में चिकित्सकों ने ग्रामीणों की स्वास्थ्य संबंधी शिकायतें सुनीं और लक्षणों के आधार पर जांच कर आवश्यक उपचार उपलब्ध कराया। शिविरों में सर्दी,खांसी,बुखार,खुजली,पेचिस सहित अन्य समस्याओं से पीड़ित मरीज पहुंचे। स्वास्थ्यकर्मियों ने मरीजों को दवाएं देने के साथ बीमारियों से बचाव के उपाय भी बताए, ग्राम निमोहर में कुल 52 मरीजों की जांच की गई। इनमें सर्दी,खांसी और बुखार से पीड़ित 24 मरीज, पेचिस का एक मरीज तथा अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से संबंधित 27 मरीज शामिल रहे, ग्राम कचोहर में 60 मरीजों का उपचार किया गया, जिनमें बुखार के 12, सर्दी-खांसी के 30 और अन्य समस्याओं के 28 मरीज शामिल थे, इसी क्रम में ग्राम देवतीडांड में सर्वाधिक 67 मरीजों की जांच की गई,इनमें सर्दी,खांसी और

मलेरिया की जांच में नहीं मिला कोई सक्रिय मामला,ग्रामीणों को किया जागरूक

मौसमी बीमारियों के बीच मलेरिया की आशंका को देखते हुए शिविरों में मरीजों की मलेरिया जांच भी की गई। विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार,जांच के दौरान मलेरिया का एक भी सक्रिय मामला सामने नहीं आया, वनांचल क्षेत्र में बुखार की शिकायतों के बीच यह राहत की बात रही,जिला मलेरिया सलाहकार रत्नेश शुक्ला ने ग्रामीणों को मलेरिया और अन्य मौसमी बीमारियों से बचाव के उपायों की जानकारी दी। उन्होंने मच्छरों से बचाव, घरों और आसपास पानी जमा नहीं होने देने, स्वच्छता बनाए रखने तथा बुखार आने पर तत्काल जांच कराने के महत्व के संबंध में जागरूक किया, स्वास्थ्य विभाग की ओर से ग्रामीणों को यह संदेश भी दिया गया कि बुखार या अन्य लक्षणों को सामान्य समझकर नजरअंदाज न करें। समय पर जांच और उचित उपचार से बीमारी की गंभीरता को कम करने में मदद मिल सकती है।

बुखार के 10,खुजली के पांच तथा अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से संबंधित 52 मरीज शामिल रहे। ग्राम बंसीपुर में 35 मरीजों को उपचार और आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराई गईं। इनमें सर्दी,खांसी और बुखार के 13 मरीज तथा अन्य समस्याओं से पीड़ित 22 मरीज शामिल थे,इस प्रकार चारों गांवों में कुल 214 मरीजों की जांच और उपचार किया गया। दुर्गम गांवों में एक साथ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने से उन ग्रामीणों को विशेष लाभ मिला, जिन्हें सामान्य परिस्थितियों में इलाज के लिए विकासखंड मुख्यालय तक पहुंचने में समय, संसाधन और आवागमन संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान,चिरायु दल ने मौके पर किया



चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों ने संभाली जिम्मेदारी-

विशेष स्वास्थ्य शिविरों में डॉ. विनीत दुबे,डॉ. अरविन्द यादव,डॉ. रेखा दीपांकर,डॉ. स्नेहा भगत और मो. गफ्फार ने मरीजों की जांच,उपचार और स्वास्थ्य संबंधी परामर्श देने में भूमिका निभाई। वहीं, शिविरों के संचालन और व्यवस्थाओं में मिथिलेश राजवाड़े,लालचंद,अनिल कपूर,सुदामा और सुचिता बेग ने सक्रिय योगदान दिया, चिकित्सा दलों के बीच कार्य विभाजन और गांवों तक पहुंचकर सेवाएं उपलब्ध कराने के प्रयास से एक ही दिन में चार दूरस्थ गांवों के मरीजों को लाभ मिला,इस दौरान उपचार के साथ रोगों की पहचान,आवश्यक दवाओं का वितरण और स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता पर भी ध्यान दिया गया।

समझाइश दी,दूरस्थ क्षेत्रों में बच्चों की नियमित स्वास्थ्य जांच और समय पर उपचार की उपलब्धता महत्वपूर्ण है,ऐसे में चिरायु दल की सक्रियता से स्कूली बच्चों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने का प्रयास किया गया।

डॉ. बलवंत सिंह के निर्देशन और डॉ. प्रियंका पांडेय के नेतृत्व में गांवों तक पहुंची सेवाएं-इस अभियान में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बलवंत सिंह के निर्देशन और खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. प्रियंका पांडेय के नेतृत्व में विभागीय अमले की सक्रियता प्रमुख रही। मौसमी बीमारियों की सूचना पर चिकित्सा दलों का गठन कर उन्हें दूरस्थ गांवों तक भेजना और एक ही दिन में चार स्थानों पर शिविर आयोजित करना ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम रहा,सोनहत जैसे वनांचल क्षेत्र में दूरी और

कठिन रास्तों के कारण समय पर इलाज प्राप्त करना कई ग्रामीणों के लिए चुनौतीपूर्ण होता है, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की टीमों का गांवों तक पहुंचना केवल मरीजों की जांच और दवा वितरण तक सीमित नहीं रहा,बल्कि इससे ग्रामीणों को बीमारी की स्थिति में समय पर चिकित्सा सहायता लेने और बचाव के उपाय अपनाने के प्रति जागरूक करने का अवसर भी मिला, चारों गांवों में आयोजित शिविरों में 214 मरीजों का उपचार, स्कूली बच्चों का चिरायु दल द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण और मलेरिया जांच में किसी सक्रिय मामले का सामने नहीं आना अभियान के प्रमुख परिणाम रहे, स्वास्थ्य विभाग की इस पहल से दूरस्थ ग्रामीणों को उनके गांव के नजदीक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हुईं और मौसमी बीमारियों की निगरानी तथा रोकथाम के प्रयासों को गति मिली।

पटाखे जैसी आवाज निकालने वाले 800 मॉडिफाइड साइलेंसर रोड रोलर से कुचले

सरगुजा पुलिस ने रक्षित केंद्र में कराया नष्टीकरण,बेचने और लगाने वालों को भी कार्रवाई की चेतावनी

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,09 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)।

बुलेंट सहित अन्य दोपहिया वाहनों में पटाखे जैसी तेज और कर्कश आवाज निकालने वाले मॉडिफाइड साइलेंसरों के खिलाफ सरगुजा पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस ने पूर्व में जब्त किए गए करीब 800 अवैध मॉडिफाइड साइलेंसरों को रक्षित केंद्र अम्बिकापुर में रोड रोलर चलवाकर नष्ट कर दिया। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि वाहनों में निर्धारित मानकों के विपरीत साइलेंसर लगाने या उनमें बदलाव करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस के अनुसार, बुलेंट और अन्य दोपहिया वाहनों में मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर तेज आवाज निकालने की शिकायतें लगातार मिल रही थीं। इसे गंभीरता से लेते हुए डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश अग्रवाल के निर्देशन में यातायात पुलिस और जिले के विभिन्न थाना-चौकियों की टीमों ने पिछले



कुछ महीनों से अभियान चलाया। इस दौरान ऐसे साइलेंसर लगे वाहनों पर कार्रवाई कर साइलेंसर निकलवाए गए और उन्हें ज्वल किया गया। इसी क्रम में जब्त किए गए लगभग 800 साइलेंसरों का विधिवत

नष्टीकरण कराया गया।
दुकानदारों और मैकेनिकों को भी चेतावनी : पुलिस ने शहर के अंटो पार्ट्स संचालकों, मैकेनिकों और गैरज संचालकों को चेतावनी दी है कि वे वाहनों में अवैध

मॉडिफाइड साइलेंसर बेचने या लगाने से दूर रहें। यदि किसी दुकान या गैरज में इस तरह की गतिविधि पाई जाती है,तो संबंधित संचालक के खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के मुताबिक, वाहन निर्माता कंपनी की ओर से लगाए गए मूल साइलेंसर में नियमों के विपरीत बदलाव करना मोटर वाहन कानून का उल्लंघन हो सकता है। ऐसे मामलों में वाहन चालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई के साथ प्रकरण न्यायालय में भी प्रस्तुत किया जा सकता है।

नियमों के अनुरूप रखें साइलेंसर : सरगुजा पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन करें और अपने वाहनों में निर्धारित मानकों के अनुरूप साइलेंसर ही रखें। तेज और कर्कश आवाज निकालने के लिए साइलेंसर में बदलाव न करें। पुलिस ने संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में भी मॉडिफाइड साइलेंसर लगे वाहनों की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।



-संवाददाता-
अम्बिकापुर,09 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)।

महिलाओं और बालिकाओं की प्रतिभा निखारने तथा उन्हें हुनरमंद बनाने के उद्देश्य से सेवा किटी समूह द्वारा स्थायी जनहित अभिरुचि केंद्र शुरू किया जा रहा है। रविवार, 11 अक्टूबर को शिवाजी चौक,गुदरी बाजार के पास सुधा वर्मा के निवास पर केंद्र का शुभारंभ महारथ श्रीमती मनुषा भगत, एमआईसी सदस्य श्रीमती रवेता गुप्ता और सेवा किटी समूह की वरिष्ठ सदस्यों की उपस्थिति में होगा। शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन से ही केंद्र में प्रशिक्षण की शुरुआत की जाएगी। पहले चरण में तीन दिवसीय रंगोली प्रशिक्षण आयोजित होगा, जिसमें रंगोली विशेषज्ञ श्रीमती चेतना मुंजे बालिकाओं और महिलाओं को प्रशिक्षण देंगी। इसमें 10 बालिकाओं और 10 महिलाओं

सहित कुल 20 प्रतिभागियों के शामिल होने की योजना है। खास बात यह है कि बालिकाओं के लिए सभी प्रशिक्षण पूरी तरह निःशुल्क रहेंगे। रंगोली प्रशिक्षण पूरा होने के बाद दशहरे के पश्चात चार दिवसीय सेल्फ मेकअप कोर्स शुरू किया जाएगा। केंद्र में प्रतिदिन दोपहर 2:30 से शाम 5 बजे तक प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के साथ विषय विशेषज्ञों द्वारा कार्डसलिंग भी की जाएगी, ताकि प्रतिभागियों को संबंधित कौशल की जानकारी के साथ अपनी रुचि और क्षमता विकसित करने का अवसर मिल सके। सेवा किटी समूह की संस्थापक वंदना दत्ता के अनुसार, अभिरुचि केंद्र को स्थायी रूप से जनहित में संचालित करने की योजना है। इसका उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं को उनकी रुचि के अनुरूप प्रशिक्षण उपलब्ध कराना तथा उनकी प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए एक साझा मंच प्रदान करना है।

लखनपुर विकासखंड में सरगुजा ओलंपिक 2026 का भव्य शुभारंभ,खिलाड़ियों में दिखाया उत्साह

- दौड़, लंबी कूद,ऊंची कूद सहित विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम
- 10 अक्टूबर तक चलेंगी प्रतियोगिताएं,विजेता खिलाड़ियों को किया जाएगा पुरस्कृत

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,09 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)।

सरगुजा जिले के आकांक्षी विकासखंड लखनपुर में गुरुवार को विकासखंड स्तरीय सरगुजा ओलंपिक 2026 का उत्साहपूर्ण वातावरण में शुभारंभ हुआ। कलेक्टर श्री अजीत वसंत एवं जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुश्री रोमा श्रीवास्तव के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में तथा जनपद पंचायत लखनपुर की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती खुशबू शास्त्री के नेतृत्व में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता का शुभारंभ जिला पंचायत सदस्य श्री विजय अग्रवाल एवं जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शशिकला सिंह ने खिलाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर किया। सरगुजा ओलंपिक के शुभारंभ अवसर पर खिलाड़ियों में विशेष उत्साह देखने को मिला। प्रतियोगिता के पहले दिन 100 मीटर, 200 मीटर एवं 400 मीटर दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक, भाला फेंक, चक्का फेंक, 4x100 मीटर रिले दौड़ तथा वॉलीबॉल सहित विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में महिला एवं पुरुष वर्ग के साथ ही जूनियर एवं सीनियर वर्ग के



खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए अपनी खेल प्रतिभा, शारीरिक क्षमता एवं खेल कौशल का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं अतिथियों ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि सरगुजा ओलंपिक जैसे खेल आयोजनों से ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों की खेल प्रतिभाओं को अपनी क्षमता प्रदर्शित करने का अवसर मिलता है। ऐसे आयोजन युवाओं में खेल भावना,अनूशासन,टीम भावना एवं स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरगुजा ओलंपिक के माध्यम से विकासखंड के विभिन्न क्षेत्रों के खिलाड़ियों को एक साझा मंच उपलब्ध कराया जा रहा है, जहां वे अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें।

मवेशी तस्करी के कथित मास्टरमाइंड जितेन्द्र जायसवाल की गिरफ्तारी,34 भैंस-भैंसे जव्त रघुनाथनगर में पुलिस की कार्रवाई,आरोपी के खिलाफ पहले से तीन मामले दर्ज,गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी

-संवाददाता-
बलरामपुर,09 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)।

बलरामपुर जिले में मवेशी तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए रघुनाथनगर पुलिस ने कथित संगठित गिरोह के स्थानीय सप्तायर जितेन्द्र जायसवाल (34) को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी ग्राम केसारी का निवासी है और मवेशियों को एकत्र कर उत्तर प्रदेश की ओर भेजने वाले नेटवर्क में उसकी अहम भूमिका थी। मामले में पुलिस पहले ही 34 भैंस और भैंसों को जब्त कर एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है। गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। गिरोह के अन्य सदस्यों के अनुसार,16 सितंबर 2026 को रघुनाथनगर पुलिस की टीम गश्त पर थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ लोग मवेशियों को पैदल उत्तर प्रदेश ले जाने की तैयारी में हैं। सूचना पर पुलिस ने ग्राम केसारी में घेराबंदी की। पुलिस को देखकर मौके पर मौजूद लोगों ने भागने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस ने दीपक सोनवानी (24) को पकड़ लिया, जबकि कुछ अन्य लोग अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। मौके से 34 भैंस और भैंसे जव्त किए गए।



स्थानीय स्तर पर मवेशी जुटाने का आरोप : पुलिस के मुताबिक, फरार आरोपियों की तलाश के लिए विशेष टीम गठित की गई थी। संभावित ठिकानों पर दबिश और मुखबिर से मिली जानकारी के आधार पर जितेन्द्र जायसवाल को

हिरासत में लेकर साक्ष्यों के आधार पर गिरफ्तार किया गया। जांच में पुलिस का दावा है कि जितेन्द्र स्थानीय स्तर पर किसानों और ग्रामीणों से कम कीमत पर मवेशी खरीदकर उन्हें जंगलों में छिपाता था। इसके बाद मौका देखकर मवेशियों

को दूसरे स्थानों तक पहुंचाया जाता था और कथित तौर पर उत्तर प्रदेश की ओर भेजा जाता था। पुलिस इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका को भी जांच कर रही है।

आरोपी के खिलाफ पहले से तीन मामले : पुलिस के अनुसार, जितेन्द्र जायसवाल के खिलाफ रघुनाथनगर थाने में मवेशी तस्करी और पशु क्रूरता से संबंधित तीन पूर्व मामले दर्ज हैं। इनमें अपराध क्रमांक 26/2026,127/2021 और 124/2025 शामिल हैं। इन मामलों में छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम, 2004 तथा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। वर्ष 2026 के मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 111(1) का भी उल्लेख है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। कार्रवाई पुलिस अधीक्षक और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, बलरामपुर के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक रवि सिंह एवं रघुनाथनगर पुलिस टीम ने की। पुलिस का कहना है कि मवेशी तस्करी के नेटवर्क को तोड़ने और फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की मौजूदगी में सोनहत को मिला 'टीबी मुक्त ब्लॉक' सम्मान खड़गवां के राज्य स्तरीय समारोह में सोनहत सहित चार विकासखंडों की उपलब्धि का उल्लेख, बीएमओ डॉ. प्रियंका पाण्डेय ने पूरी स्वास्थ्य टीम को दी बधाई....



टीबी उन्मूलन की दिशा में सोनहत की बड़ी उपलब्धि,मिला 'टीबी मुक्त ब्लॉक' का सम्मान

सोनहत ने हासिल किया टीबी मुक्त ब्लॉक का सम्मान,स्वास्थ्यकर्मियों के सामूहिक प्रयासों को मिली पहचान

स्वास्थ्य टीम की मेहनत रंग लाई, सोनहत को मिला 'टीबी मुक्त ब्लॉक' का सम्मान

टीबी के खिलाफ जंग में सोनहत की कामयाबी, राज्य स्तरीय समारोह में मिला सम्मान

**-संवाददाता-
सोनहत/एमसीबी,09 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)।**

टीबी उन्मूलन की दिशा में सोनहत विकासखंड ने महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, 8 अक्टूबर 2026 को खड़गवां के जनपद पंचायत मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सोनहत को 'टीबी मुक्त विकासखंड' का सम्मान मिला, छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की मौजूदगी में आयोजित इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग के मैदानी अमले, पंचायत प्रतिनिधियों और सामुदायिक सहभागिता के योगदान को रेखांकित किया गया, राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सोनहत के साथ एमसीबी जिले के खड़गवां, सरगुजा जिले के बतौली और रायगढ़ जिले के घरघोड़ा विकासखंड को भी टीबी मुक्त घोषित किए जाने की जानकारी सामने आई,सोनहत ब्लॉक को मिला यह सम्मान केवल स्वास्थ्य विभाग की उपलब्धि के रूप में नहीं, बल्कि बीमारी के प्रति जागरूकता बढ़ाने,संभावित मरीजों को जांच के लिए प्रेरित करने और उपचार से जोड़ने के सामूहिक प्रयासों की पहचान के तौर पर देखा जा रहा है,इस उपलब्धि से क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों

बीएमओ डॉ. प्रियंका पाण्डेय ने बताया पूरी टीम की मेहनत का परिणाम-

सोनहत ब्लॉक को 'टीबी मुक्त ब्लॉक' का सम्मान मिलने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोनहत की खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. प्रियंका पाण्डेय ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे पूरे स्वास्थ्य अमले के लिए गर्व और हर्ष का विषय बताया, उन्होंने इस उपलब्धि के लिए सोनहत ब्लॉक की समस्त स्वास्थ्य टीम को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं, डॉ. पाण्डेय के अनुसार, यह सफलता किसी एक व्यक्ति के प्रयास से नहीं, बल्कि पूरी टीम की निरंतर मेहनत, समर्पण और सामूहिक जिम्मेदारी से संभव हुई है, टीबी उन्मूलन जैसे अभियान में चिकित्सकों के साथ स्वास्थ्य कर्मचारियों और मैदानी स्तर पर काम करने वाले कर्मियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, संभावित मरीजों की पहचान, जांच के लिए प्रेरित करना, उपचार के प्रति जागरूकता बढ़ाना और मरीजों को नियमित दवा सेवन के लिए प्रोत्साहित करना इस कार्य के प्रमुख हिस्से हैं, उन्होंने स्वास्थ्य टीम से इसी तरह टीम भावना और समर्पण बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि टीबी मुक्त भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास जरूरी हैं, सम्मान मिलने के बाद भी जागरूकता, जांच और उपचार से संबंधित गतिविधियों को जारी रखना महत्वपूर्ण होगा।

का उत्साह बढ़ा है,अब चुनौती इस स्थिति को बनाए रखने और टीबी की समय पर पहचान तथा नियमित उपचार के प्रयासों को लगातार मजबूत करने की है।

खड़गवां में राज्य स्तरीय कार्यक्रम, दिल्ली से हुआ 'जोश' टीम का शुभारंभ- 'सशक्त एमसीबी सेवा संकल्प अभियान' के अंतर्गत जनपद पंचायत मैदान, खड़गवां में 8 अक्टूबर को राज्य स्तरीय टीबी मुक्त भारत अभियान,जोश टीम लॉन्च एवं टीबी मुक्त विकासखंड कार्यक्रम आयोजित किया गया, कार्यक्रम के दौरान नई दिल्ली के भारत मंडपम से आयोजित JOSH (Joint Squad for Health) टीमों के राष्ट्रीय शुभारंभ का सीधा प्रसारण किया गया,कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल रहे,राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा सहित अन्य केन्द्रीय मंत्री उपस्थित रहे,खड़गवां में आयोजित कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी-कर्मचारी,जनप्रतिनिधि,पंचायत प्रतिनिधि, स्वास्थ्यकर्मों, युवा और ग्रामीणजन शामिल हुए, कार्यक्रम का उद्देश्य टीबी उन्मूलन अभियान को जनभागीदारी से जोड़ना और युवाओं को जागरूकता गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करना रहा। जोश टीम के

माध्यम से लोगों तक टीबी से संबंधित सही जानकारी पहुंचाने,संभावित मरीजों को जांच के लिए प्रेरित करने और बीमारी को लेकर फैले भ्रम को दूर करने पर जोर दिया गया।

एमसीबी की 199 में से 177 ग्राम पंचायतों में टीबी मुक्त-राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले की स्वास्थ्य संबंधी उपलब्धियों को भी प्रमुखता से प्रस्तुत किया गया,उपलब्ध जानकारी के अनुसार, जिले की कुल 199 ग्राम पंचायतों में से 177 ग्राम पंचायतों ने टीबी मुक्त होने की उपलब्धि हासिल की है,इस उपलब्धि के लिए संबंधित ग्राम पंचायतों के सरपंचों को गोल्ड,सिल्वर और ब्रॉन्ज श्रेणियों में सम्मानित किया गया,उन्हें गांधी प्रतिमा तथा शाल-श्रीफल भेंट किए गए, कार्यक्रम में ग्राम पंचायतों,स्वास्थ्यकर्मियों, मितानिनों,आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और ग्रामीण समुदाय की भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया गया,ग्राम स्तर पर टीबी के प्रति जागरूकता बढ़ाना,संभावित मरीजों की पहचान करना और उन्हें स्वास्थ्य केंद्रों में जांच तथा उपचार के लिए प्रोत्साहित करना इस अभियान के अहम पहलू हैं,पंचायतों की भागीदारी से स्वास्थ्य विभाग को समुदाय तक पहुंचने और लोगों को बीमारी के प्रति जागरूक करने में सहयोग मिलता है।

समय पर जांच,नियमित उपचार और पोषण पर जोर-कार्यक्रम को संभावित करते



हुए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने टीबी उन्मूलन के लिए सामूहिक प्रयासों और जनभागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने अभियान में योगदान देने वाले पंचायत प्रतिनिधियों,स्वास्थ्यकर्मियों और नागरिकों के प्रयासों की सराहना की,कार्यक्रम में यह संदेश दिया गया कि टीबी के संभावित लक्षण दिखाई देने पर जांच में देरी नहीं करनी चाहिए, समय पर बीमारी की पहचान,चिकित्सकीय सलाह के अनुसार नियमित उपचार, दवा का पूरा कोर्स और पर्याप्त पोषण टीबी से लड़ने के महत्वपूर्ण आधार हैं,टीबी को लेकर समाज में फैले भ्रम और भेदभाव को दूर करना भी जरूरी है, बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को परिवार और समुदाय का सहयोग मिले,ताकि वह बिना झिझक उपचार करा सके और उपचार बीच में छोड़ने जैसी स्थिति से बचा जा सके, स्वास्थ्य विभाग की ओर से लोगों को जागरूक करने के लिए इस तरह के कार्यक्रमों को महत्वपूर्ण माना गया, क्योंकि टीबी उन्मूलन केवल चिकित्सा संस्थानों तक सीमित नहीं है। इसके लिए ग्रामीण समुदाय,पंचायत प्रतिनिधियों और स्वास्थ्यकर्मियों के बीच समन्वय भी जरूरी है।

'जोश' टीम से गांव-गांव तक पहुंचना जागरूकता का संदेश-जोश टीम लॉन्च का मुख्य उद्देश्य युवाओं की ऊर्जा को टीबी उन्मूलन अभियान से जोड़ना है,इसके माध्यम से युवाओं को सामुदायिक संपर्क, जनजागरूकता और संभावित मरीजों को जांच के लिए प्रेरित करने जैसे कार्यों में भागीदारी के

लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है,युवा स्वयंसेवकों के माध्यम से टीबी के लक्षणों, जांच की जरूरत,उपचार की निरंतरता और बीमारी से जुड़े सामाजिक भेदभाव के विषय में लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता बढ़ाने के लिए युवाओं की सहभागिता महत्वपूर्ण हो सकती है,क्योंकि वे स्थानीय समुदाय के बीच संवाद स्थापित करने में मदद कर सकते हैं, कार्यक्रम में टीबी उन्मूलन अभियान से संबंधित सूचना, शिक्षा एवं संचार सामग्री जारी की गई। इसके साथ ही एआई आधारित चैटबॉट 'खुशी अवतार' की शुरुआत की जानकारी भी दी गई, इस पहल का उद्देश्य टीबी से जुड़े सवालों और उपचार संबंधी जानकारी को डिजिटल माध्यम से लोगों तक पहुंचाना है।

स्वास्थ्य स्टॉलों के जरिए दी गई जानकारी, हितग्राहियों को मिला लाभ- कार्यक्रम स्थल पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से विभिन्न स्टॉल लगाए गए,जिनके माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं और टीबी उन्मूलन अभियान से संबंधित जानकारी दी गई,हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड, छड़ी और चश्मे भी वितरित किए गए,नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं ने टीबी जागरूकता पर आधारित नाटक प्रस्तुत किया, प्रस्तुति के माध्यम से समय पर जांच कराने, नियमित उपचार जारी रखने,पोषण पर ध्यान देने और टीबी से पीड़ित लोगों के प्रति संवेदनशील व्यवहार अपनाने का संदेश दिया गया, कार्यक्रम में इन गतिविधियों के जरिए

स्वास्थ्य सेवाओं और जनजागरूकता को एक साथ जोड़ने का प्रयास किया गया,इससे लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्राप्त करने और उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानने का अवसर मिला।

सोनहत की उपलब्धि के साथ अब निरंतरता की चुनौती- सोनहत ब्लॉक को मिला 'टीबी मुक्त ब्लॉक' का सम्मान स्वास्थ्य विभाग की टीम के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। बीएमओ डॉ. प्रियंका पाण्डेय ने पूरी टीम को बधाई देकर स्पष्ट किया कि इस सफलता के पीछे सामूहिक मेहनत और समर्पण की भूमिका रही है, हालांकि, किसी ब्लॉक को टीबी मुक्त होने का सम्मान मिलने के बाद भी बीमारी के प्रति सतत सतर्कता बनाए रखना जरूरी है, समय पर जांच,उपचार की निरंतरता, मरीजों को पोषण और सामाजिक सहयोग तथा समुदाय में जागरूकता जैसी गतिविधियों को लगातार आगे बढ़ाना होगा,सोनहत की उपलब्धि से स्वास्थ्य अमले को प्रोत्साहन मिला है। अब इस प्रयास को बनाए रखना और टीबी के संभावित मामलों की पहचान तथा उपचार की व्यवस्था को मजबूत रखना आगे की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी,कार्यक्रम में संदेश स्पष्ट रहा- टीबी उन्मूलन के लिए स्वास्थ्य विभाग के प्रयासों के साथ पंचायतों,युवाओं,परिवारों और पूरे समुदाय की भागीदारी आवश्यक है, सामूहिक जिम्मेदारी और निरंतर जागरूकता के जरिए ही टीबी मुक्त भारत के लक्ष्य को मजबूती दी जा सकती है।



लोकतंत्र के लिए 'काला दिवस' मनाकर ब्लॉक कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन,काली पट्टी बांधकर जताया आक्रोश मतदाता सूची और निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग, राजीव भवन से पैदल मार्च निकालकर कुमार चौक पहुंचे कांग्रेसजन

**-संवाददाता-
बैकुंठपुर,09 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)।**

भारतीय लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं की रक्षा तथा निर्वाचन प्रक्रिया में जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग को लेकर 8 अक्टूबर को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बैकुंठपुर शहर ने 'काला दिवस' मनाते हुए विरोध प्रदर्शन किया,कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने काली पट्टी बांधकर अपना विरोध दर्ज कराया। इसके बाद राजीव भवन स्थित कांग्रेस कार्यालय से पैदल मार्च निकालकर कुमार चौक तक पहुंचे। कांग्रेस नेताओं ने निर्वाचन प्रक्रिया और मतदाता सूची से जुड़े सवालों पर जवाबदेही की मांग उठाई, पार्टी का आरोप है कि देश में कथित 'वोट चोरी' के मुद्दे पर सवाल पूछने वाले विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, कांग्रेस नेताओं ने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े सवालों पर जवाब देना लोकतांत्रिक व्यवस्था की जिम्मेदारी है।

दिल्ली की घटनाओं के विरोध में प्रदर्शन- ब्लॉक कांग्रेस ने दिल्ली में 6 और 7 अक्टूबर को हुए घटनाक्रम का उल्लेख करते हुए कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष रहलू गांधी,प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित इंडिया गठबंधन के सांसदों ने निर्वाचन आयोग से मुलाकात कर मतदाता सूची और निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े सवालों पर जवाबदेही की मांग की थी, कांग्रेस का आरोप है कि इस दौरान विपक्षी नेताओं

को रोकने और हिरासत में लेने की कार्रवाई की गई, पार्टी ने इसे लोकतांत्रिक संवाद और सवाल पूछने के अधिकार से जुड़ा विषय बताते हुए विरोध दर्ज कराया।

पारदर्शिता और जवाबदेही की उठाई मांग- प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसजनों ने निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने,मतदाता सूची से जुड़े सवालों का स्पष्ट जवाब देने और लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति जवाबदेही बनाए रखने की मांग उठाई, पार्टी का कहना है कि निष्पक्ष निर्वाचन व्यवस्था पर जनता का भरोसा लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया और पैदल मार्च के माध्यम से अपनी मांगों को सामने रखा।

बड़ी संख्या में कांग्रेसजन रहे उपस्थित- विरोध प्रदर्शन में जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता, पीसीसी सदस्य योगेश शुक्ला, पूर्व जिला अध्यक्ष नजीर अजहर, महामंत्री बृजवासी तिवारी, हेमसागर यादव, प्रवीर भट्टाचार्य, ब्लॉक अध्यक्ष आशीष यादव 'लल्ला', शैलेन्द्र सिंह, अजय सिंह, ज्ञानप्रत कुंरें, दीपक गुप्ता, रिजजउद्दीन, विकास शर्मास्तव, धीरज सिंह, आशीष डवरे, अंकित गुप्ता, वक्तेश जायसवाल, रहलू गुप्ता, विपुल शुक्ला, विनोद शर्मा, प्रशांत सिंह, सोरभ गुप्ता, मोहम्मद शम्बीर, बाबी, ममता गुप्ता, मनजिंदर कौर, अर्चना सिंह, यासीन, प्रमोद मिश्रा, शंकर सुमन मिश्रा, प्रखर जायसवाल, संजय पांडे, आकाश खटीक, एस. मिश्रा, अमित दुबे, अकिल बाबु, शालू सिंह और इब्राहिम इराकी सहित अनेक कांग्रेसजन उपस्थित रहे।

आईसेक्ट की कौशल विकास यात्रा पहुंची सोनहत,विद्यार्थियों को शिक्षा,कौशल और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की दी जानकारी 'समर्थ भारत-सक्षम भारत' की थीम पर आयोजित अभियान में करियर अवसरों से लेकर भविष्य की तकनीकों तक हुई चर्चा,एआई साक्षरता मिशन रहा प्रमुख आकर्षण



**-संवाददाता-
सोनहत,09 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)।**

शिक्षा, कौशल विकास और रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण के क्षेत्र में कार्यरत आईसेक्ट द्वारा आयोजित कौशल विकास यात्रा-2026 के तहत गुरुवार को सोनहत के शासकीय नवीन महाविद्यालय में जागरूकता एवं विद्यार्थी संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, कार्यक्रम में विद्यार्थियों को कौशल आधारित शिक्षा, करियर के अवसर,कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा आईसेक्ट की विभिन्न शैक्षणिक एवं कौशल विकास पहलों की जानकारी दी गई। 'समर्थ भारत-सक्षम भारत' की थीम पर आधारित आईसेक्ट की यह कौशल विकास यात्रा 5 अक्टूबर से 5 नवंबर 2026 तक देशभर में संचालित की जा रही है, अभियान के माध्यम से देश के 20 राज्यों और 300 जिलों में विद्यार्थियों, युवाओं,शिक्षकों तथा शैक्षणिक संस्थानों के बीच शिक्षा, कौशल विकास और भविष्य की तकनीकों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं।

विद्यार्थियों से हुआ सीधा संवाद- सोनहत महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों से संवाद करते हुए उन्हें करियर मार्गदर्शन,कौशल आधारित शिक्षा

और विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों की जानकारी दी गई,विद्यार्थियों को आईसेक्ट समूह की शैक्षणिक पहलों,उपलब्ध पाठ्यक्रमों और भविष्य में करियर की संभावनाओं से परिचित कराया गया,कार्यक्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, बदलते रोजगार परिदृश्य,व्यावहारिक कौशल तथा विद्यार्थियों की रुचि और योग्यता के अनुरूप शैक्षणिक विकल्पों पर भी जानकारी साझा की गई,विद्यार्थियों को क्यूआर कोड के माध्यम से पंजीयन करने तथा आगे की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मूल अवधारणाओं से कराया परिचित- कौशल विकास यात्रा-2026 का प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों और युवाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रति जागरूकता बढ़ाना भी है, इसी क्रम में आईसेक्ट के एआई साक्षरता मिशन के अंतर्गत कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मूल अवधारणाओं,शिक्षा एवं दैनिक जीवन में इसके उपयोग तथा एआई उपकरणों के जिम्मेदार और नैतिक इस्तेमाल के बारे में जानकारी दी जा रही है,इसके साथ ही 'एआई में भविष्य' विषय के अंतर्गत कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े उभरते करियर विकल्पों, भविष्य में आवश्यक कौशल,सीखने के विभिन्न मार्गों तथा एआई आधारित कार्यक्षेत्रों



के लिए जरूरी तैयारियों के बारे में भी विद्यार्थियों को बताया जा रहा है। **रोजगार की जरूरतों के अनुरूप कौशल पर जोर-**आईसेक्ट की कौशल विकास यात्रा के दौरान विद्यार्थियों को विभिन्न कौशल आधारित पाठ्यक्रमों और शैक्षणिक पहलों की जानकारी भी दी जा रही है, इनमें भविष्य के कौशल,एनीमेशन एवं दूर्य-श्रम्य तथा गेमिंग क्षेत्र,शिक्षकों एवं प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण,लेखांकन सॉफ्टवेयर प्रशिक्षण और फैशन एवं इंटीरियर डिजाइन से जुड़े कौशल विकास अवसर शामिल हैं, इसके अलावा विद्यार्थियों को कौशल आधारित पाठ्यक्रमों,नियमित एवं निजी कार्यक्रमों,ऑनलाइन स्नातक एवं स्नातकोत्तर कार्यक्रमों तथा ऑनलाइन और मिश्रित अध्ययन के विकल्पों की जानकारी दी जा रही है, आईसेक्ट समूह के विश्वविद्यालयों में उपलब्ध परिसर आधारित डिग्री कार्यक्रमों से भी विद्यार्थियों को परिचित कराया जा रहा है।

500 शैक्षणिक संस्थानों तक पहुंचने का लक्ष्य- आईसेक्ट की कौशल विकास यात्रा-2026 के माध्यम से लगभग 500 स्कूलों, कॉलेजों एवं शैक्षणिक संस्थानों तक पहुंचने तथा लगभग 1,000 आईसेक्ट कौशल ज्ञान प्रदाताओं और केंद्रों का भ्रमण

करने का लक्ष्य रखा गया है,आईसेक्ट के प्रतिनिधि ने कहा कि कौशल विकास यात्रा केवल एक शैक्षणिक अभियान नहीं है,बल्कि युवाओं को भविष्य की तकनीकों,कौशल आधारित शिक्षा और रोजगारोन्मुख अवसरों से जोड़ने की महत्वपूर्ण पहल है,इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को उनकी शैक्षणिक रुचि और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप सही विकल्पों तथा कौशल के प्रति जागरूक करना है, महाविद्यालय के प्राचार्य श्री शैलेश कुमार मिश्रा ने आईसेक्ट की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि एआई साक्षरता मिशन और कौशल विकास यात्रा विद्यार्थियों को नई तकनीकों को समझने, करियर की संभावनाएं तलाशने तथा भविष्य के लिए आवश्यक कौशल विकसित करने की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है,आईसेक्ट का यह अभियान स्कूलों, कॉलेजों, आईसेक्ट केंद्रों और स्थानीय हितधारकों के समन्वय से विद्यार्थियों तक शिक्षा, कौशल विकास और तकनीकी जागरूकता से जुड़ी जानकारी पहुंचाने पर केंद्रित है, 'समर्थ भारत-सक्षम भारत' की भावना के अनुरूप यह पहल युवाओं को अपनी रुचि,योग्यता और करियर लक्ष्य के अनुसार शैक्षणिक विकल्प समझने तथा भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल विकसित करने के लिए प्रेरित कर रही है।



जेल में बंदी सुरक्षा, पुलिस परिवार के घर जले दीप, प्रधान आरक्षक ने साझा किया दर्द...

सूरजपुर दोहरे हत्याकांड में सजा के बाद जेल प्रशासन की अगली कार्रवाई पर नजर

फांसी की सजा के बाद कुलदीप साहू की सुरक्षा बढ़ी, रायपुर जेल शिफ्टिंग की प्रक्रिया शुरू

एक फैसले से लौटा इंसाफ का भरोसा, पुलिस परिवार ने जलाए दीप, तीन दोषियों को मृत्युदंड, मुख्य आरोपी की सुरक्षा बढ़ी मृत्युदंड के बाद कुलदीप पर कड़ी निगरानी, रायपुर जेल की तैयारी

अंबिकापुर जेल अधीक्षक ने बताया-आगे की कार्रवाई न्यायालय के निर्देश पर

अदालत के फैसले पर पुलिस लाइन में दिवाली, प्रधान आरक्षक ने की भावुक पोस्ट

मां-बेटी हत्याकांड में तीन को मृत्युदंड, एक को मृत्यु पर्यंत कारावास

अंबिकापुर केंद्रीय जेल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई पेशी, जेल अधीक्षक बोले-आगे की कार्रवाई न्यायालय के निर्देश और जेल नियमावली के तहत

10 साल की सजा के बाद कोर्ट से मुक्त होकर निकला था कुलदीप, मृत्युदंड की खबर पर इस बार प्रतिक्रिया अलग, पुलिस कॉलोनी में फैसले का स्वागत

-संवाददाता- अंबिकापुर/सूरजपुर, 09 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)।

सूरजपुर के बहुचर्चित मां-बेटी दोहरे हत्याकांड में मृत्युदंड की सजा सुनाए जाने के बाद मुख्य दोषी कुलदीप साहू को अंबिकापुर केंद्रीय जेल से रायपुर केंद्रीय जेल स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू होने की जानकारी सामने आई है,

जेल अधीक्षक ने क्या बताया?-

केंद्रीय जेल अंबिकापुर के जेल अधीक्षक अक्षय सिंह राजपूत ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि दोषियों को न्यायालय के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था, इसी माध्यम से कुलदीप साहू को सजा सुनाए जाने की जानकारी मिली, पत्रकारों ने जब बंदी की प्रतिक्रिया के बारे में पूछा, तो जेल अधीक्षक ने बताया कि इस बार उसकी प्रतिक्रिया पहले जैसी नहीं थी और वह कुछ नकारात्मक दिखाई दिया, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वह स्वयं न्यायालय में मौजूद नहीं थे, इसलिए वहां बंदी के चेहरे के भावों के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी देने की स्थिति में नहीं थे, जेल अधीक्षक के अनुसार, मृत्युदंड की सजा के बाद बंदी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, आगे की कार्रवाई निर्धारित जेल प्रक्रिया और न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप की जाएगी।

रायपुर केंद्रीय जेल में फांसी की व्यवस्था होने के कारण यह कदम आगे की जेल प्रक्रिया से जुड़ा बताया जा रहा है, फिलहाल कुलदीप अंबिकापुर केंद्रीय जेल में बंद है, जेल प्रशासन ने उसकी सुरक्षा बढ़ा दी है और आगे की कार्रवाई न्यायालय के निर्देशों तथा जेल नियमावली के अनुसार किए जाने की बात कही है, इस संबंध में 8 अक्टूबर को प्रकाशित रिपोर्टों में भी रायपुर जेल स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू होने की जानकारी दी गई है, 8 अक्टूबर को सूरजपुर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने प्रधान आरक्षक की पत्नी और नाबालिग बेटी की हत्या के मामले में कुलदीप साहू, फूल सिंह उर्फ रिकू सिंह और चंद्रकांत चौधरी को मृत्युदंड सुनाया, जबकि आर्यन विश्वकर्मा उर्फ गोल्डी को मृत्यु पर्यंत कारावास की सजा दी, अदालत का यह फैसला मामले की न्यायिक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण पड़ाव है, हालांकि, मृत्युदंड के क्रियान्वयन से पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की पुष्टि आवश्यक है।

रायपुर जेल में स्थानांतरण की तैयारी, लेकिन फांसी की प्रक्रिया अभी नहीं- पत्रकारों ने जेल अधीक्षक से पूछा कि अंबिकापुर केंद्रीय जेल में फांसी देने की व्यवस्था उपलब्ध है या नहीं, इस पर उन्होंने बताया कि प्रदेश में फांसी की व्यवस्था रायपुर केंद्रीय जेल में है, ऐसे में आगे की प्रक्रिया के तहत बंदी को रायपुर स्थानांतरित किया जा सकता है, यहां एक कानूनी अंतर समझना जरूरी

है, रायपुर जेल स्थानांतरण की तैयारी का अर्थ यह नहीं है कि मृत्युदंड का क्रियान्वयन निकट है या उसकी तारीख तय हो गई है, अदालत के आदेश के अनुसार, तीनों दोषियों को सुनाई गई मृत्युदंड की सजा छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की पुष्टि होने तक निष्पादित नहीं की जा सकती, इसलिए फिलहाल जेल प्रशासन की कार्रवाई को सुरक्षा, स्थानांतरण और नियमानुसार व्यवस्था के संदर्भ में देखना चाहिए, मृत्युदंड के क्रियान्वयन से संबंधित आगे की प्रक्रिया न्यायिक पुष्टि और निर्धारित कानूनी कदमों पर निर्भर करेगी।

29 सितंबर को मुस्कुराते हुए बाहर आया था कुलदीप- कुलदीप साहू के व्यवहार को लेकर 29 सितंबर को भी चर्चा हुई थी, उस दिन पुलिसकर्मियों को वाहन से कुचलने के प्रयास से जुड़े एक अलग मामले में उसे 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी, इसके बाद वह न्यायालय परिसर से बाहर पर प्रसारित हुआ और लोगों ने इस पर प्रतिक्रियाएं दी थीं, अब मां-बेटी हत्याकांड में मृत्युदंड सुनाए जाने के बाद जेल अधीक्षक ने बंदी की प्रतिक्रिया पहले से अलग होने की बात कही है, हालांकि, चेहरे के भावों के आधार पर किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति के बारे में निश्चित निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा, इस मामले में पुष्ट तथ्य यही है कि अलग-अलग



मामलों में सजा सुनाए जाने के बाद कुलदीप के सार्वजनिक व्यवहार को लेकर चर्चा हुई है। पुलिस परिवार ने फैसले का स्वागत किया, पुलिस कॉलोनी में जले दीप-सजा सुनाए जाने के बाद सूरजपुर में पुलिस परिवार और पुलिस लाइन से जुड़े लोगों ने फैसले का स्वागत किया, उपलब्ध स्थानीय जानकारी के अनुसार, पुलिस कॉलोनी में रहने वाले कुछ परिवारों ने घरों के सामने दीप जलाए और पटाखे फोड़कर खुशी जताई, फैसले वाली शाम पुलिस लाइन और कॉलोनी में उत्सव जैसा माहौल दिखाई दिया, प्रधान आरक्षक के परिवार के साथ हुई घटना के बाद पुलिस महकमे और स्थानीय लोगों में गहरा आक्रोश था, ऐसे में अदालत से सजा सुनाए जाने को कई लोगों ने न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना, हालांकि, इस खुशी के बीच उस परिवार की अपूरणीय क्षति भी बनी हुई है, जिसने इस घटना में अपने प्रियजनों को खो दिया, यह प्रतिक्रिया केवल सजा पर संतोष व्यक्त करने का अवसर नहीं, बल्कि उस लंबे इंतजार की भी याद दिलाती है जिसमें पीड़ित परिवार और पुलिस महकमे को

न्यायिक फैसले की प्रतीक्षा करनी पड़ी। प्रधान आरक्षक की सोशल मीडिया पोस्ट भी चर्चा में-फैसले के बाद प्रधान आरक्षक तालिब शेख की सोशल मीडिया पोस्ट भी चर्चा में आई, पोस्ट में न्याय, संघर्ष और कठिन समय में उम्मीद बनाए रखने जैसे भाव व्यक्त किए गए हैं, यह प्रतिक्रिया मामले से जुड़े परिवार के भावनात्मक पक्ष को सामने लाती है, हालांकि, पोस्ट के आधार पर परिवार की पूरी मनोदशा या उसकी ओर से किसी औपचारिक बयान का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, इस फैसले के बाद सामने आई व्यक्तिगत प्रतिक्रिया के रूप में ही देखा जाना उचित होगा। चार दोषियों की सजा में अंतर, अदालत के तर्क महत्वपूर्ण-इस मामले में तीन दोषियों को मृत्युदंड और आर्यन विश्वकर्मा उर्फ गोल्डी को मृत्यु पर्यंत कारावास दिया गया है, सजा में इस अंतर को लेकर चर्चा हो रही है, सजा तय करते समय अदालत प्रत्येक दोषी की भूमिका, अपराध की परिस्थितियों, उपलब्ध साक्ष्यों और कानून के

निर्धारित सिद्धांतों पर विचार करती है, इसलिए चारों दोषियों को अलग-अलग सजा दिए जाने के कारणों को समझने के लिए न्यायालय के विस्तृत फैसले में दर्ज तर्कों का इंतजार है। अब आगे की निगाहें न्यायिक प्रक्रिया पर-सूरजपुर के दोहरे हत्याकांड में निचली अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है, तीन दोषियों को मृत्युदंड और एक को मृत्यु पर्यंत कारावास दिया गया है, अब मृत्युदंड की हाईकोर्ट से पुष्टि और अन्य संबंधित कानूनी प्रक्रियाएं महत्वपूर्ण होंगी, इधर, अंबिकापुर केंद्रीय जेल में सुरक्षा बढ़ाए जाने और रायपुर जेल स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू होने की जानकारी के बीच जेल प्रशासन ने नियमों के अनुरूप कार्रवाई करने की बात कही है, फिलहाल दो बातें स्पष्ट हैं-कुलदीप साहू की सुरक्षा बढ़ाई गई है और रायपुर जेल स्थानांतरण की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, लेकिन मृत्युदंड का क्रियान्वयन हाईकोर्ट की पुष्टि तथा निर्धारित कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही संभव होगा।

शब्दों के पते, ज्ञान के बीज और सपनों का वृक्ष, चट्टीडांड में अनूठे अंदाज में शुरू हुआ 'शब्दबीज' नवाचार

बच्चों ने शब्दबीज पेटी से निकाले शब्दों के पते, खेल-खेल में सीखने की पहल... 'छोटे पाँव मजबूत कदम' संस्था ने शब्दबीज डायरी के लिए उपलब्ध कराई कॉपियां

-संवाददाता- सूरजपुर, 09 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)।

कहीं हाथों में शब्दों के पते, कहीं चेहरों पर मुस्कान, तो कहीं कुछ नया सीखने की उत्सुकता। शासकीय प्राथमिक शाला चट्टीडांड में जिला स्तरीय शैक्षिक नवाचार 'शब्दबीज' का शुभारंभ अनूठे अंदाज में किया गया। यहां बच्चों ने शब्दबीज पेटी से अपनी कक्षा के स्तर के अनुरूप शब्द लिखे पते निकाले और शब्दों को समझने, पढ़ने तथा अपने दैनिक जीवन में उनका प्रयोग करने की नई यात्रा शुरू की। यह गतिविधि महज एक कार्यक्रम का शुभारंभ नहीं, बल्कि बच्चों में भाषा सीखने के प्रति रुचि जगाने और शिक्षा को अधिक रोचक एवं व्यवहारिक बनाने की पहल के रूप में सामने आई। नवाचार के माध्यम से शब्दों को केवल किताबों के पन्नों तक सीमित रखने के बजाय बच्चों के अनुभव, संवाद और दैनिक जीवन से जोड़ने का संदेश दिया गया।

शब्दबीज पेटी बनी बच्चों के आकर्षण का केंद्र- कार्यक्रम में शब्दबीज पेटी के माध्यम से बच्चों को शब्दों से परिचित कराने की गतिविधि आयोजित की गई, बच्चों ने उत्साह के साथ अपनी कक्षा के अनुरूप शब्दों के पते निकाले। इस प्रक्रिया ने शब्द सीखने को एक रोचक गतिविधि में बदल दिया, जिसमें बच्चों की सहभागिता और जिज्ञासा प्रमुख रही, 'शब्दबीज' का उद्देश्य बच्चों को केवल शब्द याद कराना नहीं, बल्कि उन्हें शब्दों का अर्थ



समझने, सही उच्चारण करने, पढ़ने-लिखने और बातचीत में उनका उपयोग करने के लिए प्रेरित करना है, प्रारंभिक कक्षाओं में भाषा की मजबूत नींव आगे की पढ़ाई के लिए महत्वपूर्ण होती है। शब्दों की बेहतर समझ से बच्चों को पाठ समझने, प्रश्नों के उत्तर देने, अपने विचार व्यक्त करने और कक्षा की गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी करने में मदद मिलती है।

शब्दबीज डायरी में संजोए गए नए शब्द- नवाचार को नियमित अभ्यास से जोड़ने के लिए विद्यालय के प्रधानाचार्य गौतम शर्मा की पहल पर 'छोटे पाँव मजबूत कदम' संस्था ने बच्चों को शब्दबीज डायरी तैयार करने के लिए कॉपियां उपलब्ध कराईं, इन कॉपियों में बच्चे नए शब्दों को लिखकर उनका संग्रह तैयार कर सकेंगे,

शब्दबीज डायरी बच्चों के लिए केवल लिखने की कापी नहीं, बल्कि भाषा सीखने की यात्रा का साथी बनने की परिकल्पना के साथ शुरू की गई है, निर्माण रूप से शब्द लिखने, उन्हें समझने और दोहराने से बच्चों को अपने शब्द भंडार को बढ़ाने का अवसर मिलेगा, साथ ही वे सीखे गए शब्दों का उपयोग बोलचाल और लेखन में करने का अभ्यास कर सकेंगे।

शब्दबीज सूत्र से शब्दवीर सम्मान तक की जानकारी-शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान बच्चों को शब्दबीज नवाचार की अवधारणा, उद्देश्य और कार्यप्रणाली से विस्तारपूर्वक परिचित कराया गया। उन्हें शब्दबीज सूत्र, शब्दबीज पट्ट, शब्दबीज डायरी, शब्द उत्सव, शब्दबीज संवर्धक और शब्दवीर सम्मान के बारे में जानकारी दी



गई, इन गतिविधियों का उद्देश्य शब्द सीखने की प्रक्रिया को निरंतर अभ्यास, सहभागिता और प्रोत्साहन से जोड़ना है, शब्दों को पढ़ना, उनका अर्थ समझना, सही तरीके से बोलना और व्यवहार में इस्तेमाल करना भाषा सीखने के महत्वपूर्ण चरण हैं, नवाचार इसी प्रक्रिया को सजा पर संतोष व्यक्त करने का अवसर नहीं, बल्कि उस लंबे इंतजार की भी याद दिलाती है जिसमें पीड़ित परिवार और पुलिस महकमे को

भाषा की मजबूत नींव से आगे बढ़ेंगे बच्चों- प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर भाषा संबंधी दक्षता विकसित करना बच्चों की शैक्षणिक प्रगति में अहम भूमिका निभाता है, यदि बच्चा शब्दों को समझने और अपने विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में सक्षम होता है, तो उसे अन्य विषयों को समझने में भी सहायता मिलती है, 'शब्दबीज'

के माध्यम से बच्चों को सीखने की ऐसी प्रक्रिया से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें वे केवल सुनने या याद करने तक सीमित न रहें, बल्कि स्वयं गतिविधियों में भाग लेकर सीखें, शब्दों के पते निकालना, उन्हें डायरी में लिखना और उनका अर्थ समझना बच्चों में पढ़ने-लिखने की आदत को प्रोत्साहित करने का माध्यम बन सकता है।

शिक्षा में नवाचार को मिला सामूहिक सहयोग- कार्यक्रम में शाला प्रबंधन समिति की अध्यक्ष चन्द्रलेखा पालक शिक्षक समिति की अध्यक्ष श्रीमती आशा, सहायक जिला नोडल विजय बरगाह, सहायक जिला नोडल कुमारी टेसु सुमन तथा शिक्षिका मंजू कुंजर उपस्थित रहीं, चट्टीडांड की शासकीय प्राथमिक शाला में शुरू



हुई यह पहल बच्चों को शब्दों से जोड़ने के साथ भाषा सीखने को आनंददायक बनाने का संदेश देती है, शब्दबीज पेटी से निकाला प्रत्येक शब्द बच्चों के लिए नई जानकारी और अभ्यास का अवसर बन सकता है, नियमित गतिविधियों, शब्दबीज डायरी और शिक्षकों के मार्गदर्शन से पढ़ने-लिखने की आदत को प्रोत्साहित करने का माध्यम बन सकता है।

महासमुंद में पकड़ाया 2.80 करोड़ का गांजा

महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ होते हुए ओडिशा खपाने ले जा रहे थे,नाकेबंदी कर पुलिस ने पकड़ा

महासमुंद,09 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में 2 करोड़ 80 लाख रुपए का गांजा पकड़ा गया है। महाराष्ट्र के 2 तस्कर मिनी ट्रक में 560 किलो गांजा छिपाकर ओडिशा खपाने ले जा रहे थे। मुखबिर की सूचना के बाद पुलिस ने एनएच-53 पर रेहटीखोल में नाकेबंदी कर उन्हें पकड़ा। तस्करों ने खाली कैरेट के पीछे बोरियों में गांजा भरा था। पुलिस ने कुल 16 बोरियां पकड़ी हैं। पुलिस ने गाड़ी जब्त कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों महाराष्ट्र के ही रहने वाले हैं। मामला सिंचोड़ थाना क्षेत्र का है।

मुखबिर की सूचना पर एनएच-53 में नाकेबंदी

पुलिस के मुताबिक,मुखबिर ने माजदा (MH 18 BG 7546) में गांजा ले जाए जाने की जानकारी दी थी। सूचना मिलते ही संयुक्त टीम ने नेशनल हाइवे-53 पर रेहटीखोल के पास निगरानी बढ़ाई और आने-जाने वाले वाहनों की जांच शुरू कर दी। कुछ देर बाद मुखबिर के बताए हुलिए और नंबर वाला वाहन वहां पहुंचा। पुलिस ने गाड़ी रोककर तलाशी ली। उसमें दो लड़के सवार थे। पूछताछ में उन्होंने अपनी पहचान अजय रविन्द्र पवार (30) और



कैरेट के नीचे 16 बोरियों में छिपाया था गांजा

पुलिस के अनुसार, शुरुआती पूछताछ में दोनों आरोपी गोलमोल जवाब देते रहे। सख्ती से पूछताछ करने पर उन्होंने वाहन के डाले में रखे कैरेट के नीचे बोरियों में गांजा छिपाकर ले जाने की बात स्वीकार की। इसके बाद पुलिस ने वाहन की तलाशी ली तो कैरेट के नीचे 16 बोरियां मिलीं। हर एक बोरी में करीब 35-35 किलो गांजा भरा हुआ था। तौल करने पर गांजे की कुल मात्रा 560 किलो निकली। पुलिस ने गांजे को जब्त कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

2 करोड़ 80 लाख का गांजा जब्त

जब्त गांजे की कीमत करीब 2 करोड़ 80 लाख रुपए बताई गई है। तस्करों में इस्तेमाल आयशर माजदा वाहन और दो मोबाइल फोन समेत कुल 2 करोड़ 95 लाख 8 हजार रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। ये कार्रवाई एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स और सिंचोड़ पुलिस की संयुक्त थी।

स्वराज महाजन (25) बताया। दोनों महाराष्ट्र के ही रहने वाले हैं।

ओडिशा से महाराष्ट्र ले जा कर खपाना था गांजा

पूछताछ में आरोपियों ने गांजा ओडिशा के बरहमपुर से लोड कर महाराष्ट्र के जलगांव ले जाना बताया। पुलिस अब इस तस्करी के नेटवर्क की जांच कर रही है। गांजा कहा से लाया गया था, इसकी आपूर्ति में कौन-कौन शामिल है और इसे आगे किन लोगों तक पहुंचाया जाना था, इन बिंदुओं पर भी जानकारी जुटाई जा रही है। सिंचोड़ पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीएस एक्ट की धारा 20(बी)(II)(सी) के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।

2.95 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त

पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 560 किलो गांजा, करीब 15 लाख रुपए कीमत का आयशर माजदा वाहन और दो मोबाइल फोन जब्त किए हैं। पुलिस के मुताबिक, जब्त गांजे की कीमत करीब 2 करोड़ 80 लाख रुपए है। वाहन और मोबाइल समेत कुल जब्त संपत्ति का मूल्य 2 करोड़ 95 लाख 8 हजार रुपए बताया गया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार,जिले में मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसमें गांजे के स्रोत से लेकर उसकी आपूर्ति और अंतिम गंतव्य तक निगरानी रखने के साथ वित्तीय जांच भी की जा रही है।

+ 17 साल से ज्यादा उम्र के युवा भर सकेंगे फॉर्म-6

छत्तीसगढ़ में छूटे मतदाताओं के नाम जोड़ने विशेष अभियान शुरू

रायपुर,09 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए एक महीने का विशेष अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत जिन लोगों का नाम अब तक मतदाता सूची में नहीं जुड़ पाया है, उनका सत्यापन कर नाम जोड़ने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पहली बार वोट देने वाले युवाओं पर खास ध्यान दिया जाएगा। 17 साल से अधिक उम्र के युवा भी फॉर्म-6 भरकर आवेदन कर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यशवंत कुमार ने प्रेस वार्ता में अभियान की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर यह अभियान चलाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य सभी पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में जोड़ना है। उन्होंने 18 साल की उम्र पूरी कर चुके सभी पात्र नागरिकों से मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने की अपील की।

हर समाह मतदान केंद्रों और शिक्षण संस्थानों में लगेगे शिविर : मतदाता पंजीकरण के लिए हर साप्ताह बुधवार और गुरुवार को मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे। वहीं, शुक्रवार और शनिवार को स्कूल-कॉलेजों में पंजीकरण अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत आईटीआई,हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल और उच्च शिक्षण संस्थानों में शिविर लगाए जाएंगे। इन संस्थानों में बने इलेक्टोरल लिटरसी क्लब के जरिए युवाओं को मतदाता पंजीकरण के बारे में जानकारी दी जाएगी और उन्हें



जागरूक किया जाएगा। अभियान के दौरान मतदाता सूची से अलग-अलग कारणों से हटाए गए नामों का भी दोबारा सत्यापन किया जाएगा। बूथ लेवल अधिकारियों को फॉर्म-6 भरवाने और अपने क्षेत्र में मतदाताओं का सत्यापन कर रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्वाचक रजिस्ट्रारण अधिकारी मतदाता सूची की जानकारी राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों के साथ भी साझा करेंगे,ताकि पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने की प्रक्रिया में मदद मिल सके। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए नागरिक ECINET मोबाइल ऐप और आधिकारिक वेबसाइट voters.eci.gov.in के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जो लोग ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते,वे अपने क्षेत्र के मतदान केंद्र के बूथ लेवल अधिकारी को फॉर्म-6 देकर आवेदन कर सकते हैं।

धर्म-स्वातंत्र्य अधिनियम को चुनौती,हाईकोर्ट ने मांगा जवाब...कानून की संवैधानिकता पर पहले से याचिकाएं लंबित,राज्य सरकार को 3 हफ्ते में देना होगा जवाब

बिलासपुर,09 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, 2026 के प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है। चीफ जस्टिस कृष्ण राम महापात्र और जस्टिस संतोष शर्मा की बेंच ने कहा है कि अंतरिम आवेदन पर भी अगली सुनवाई में दोनों पक्षों को सुनने के बाद विचार किया जा सकता है। अब इस मामले की अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी। वीएन प्रसाद राव ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट ने पक्ष रखा, जबकि राज्य सरकार की ओर से शासकीय अधिवक्ता राहुल तामस्कर ने पैरवी की। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, 2026 के अलग-अलग प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली दूसरी याचिकाएं भी हाईकोर्ट में लंबित हैं। सरकार ने इसी आधार पर मौजूदा मामले में नोटिस जारी करने का अनुरोध किया। वहीं,याचिकाकर्ता की ओर से अंतरिम आवेदन पर अलग से सुनवाई करने और सरकार को तैयारी के लिए कम समय देने की मांग की गई। दूसरी ओर, राज्य सरकार ने अपना जवाब पेश करने के लिए तीन सप्ताह का समय मांगा।



साइबर अपराधों से सुरक्षा के लिए जनभागीदारी जरूरी,साइबर जागरूकता को जनआंदोलन बनाना होगा : सीएम साय

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय साइबर जागृति अभियान एवं ट्रैफिक हैकार्थॉन-2026 के अभिनंदन समारोह में हुए शामिल

रायपुर,09 अक्टूबर 2026। डिजिटल युग में साइबर अपराध एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आए हैं और इनसे सुरक्षित रहने का सबसे प्रभावी माध्यम जागरूकता, सतर्कता और जनभागीदारी है। साइबर सुरक्षा केवल शासन और पुलिस की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक नागरिक की साझा जिम्मेदारी है।

हमें साइबर जागरूकता को जनआंदोलन का स्वरूप देना होगा, तभी हम साइबर ठगी और डिजिटल अपराधों से सुरक्षित छत्तीसगढ़ के संकल्प को साकार कर सकेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज राजधानी रायपुर के पीडित दिनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा आयोजित 'साइबर जागृति अभियान एवं ट्रैफिक हैकार्थॉन-2026' के अभिनंदन समारोह में संबोधित करते हुए यह बात कही। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डिजिटल इंडिया ने देश में अभूतपूर्व परिवर्तन किया है। वर्ष 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी ने

डिजिटल इंडिया की परिकल्पना प्रस्तुत की थी,उस समय इतने विशाल देश और बड़ी ग्रामीण आबादी के बीच डिजिटल अर्थव्यवस्था की सफलता को लेकर अनेक आशंकाएं व्यक्त की जाती थीं। आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। गांव का सामान्य नागरिक भी मोबाइल फोन के माध्यम से डिजिटल भुगतान कर रहा है और तकनीक के जरिए देश-दुनिया से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि डिजिटल सुविधाओं के विस्तार ने जहां नागरिकों के जीवन को आसान बनाया है,वहीं साइबर ठगी और डिजिटल अपराधों की चुनौतियां भी बढ़ी हैं। अपराधी नई-नई तकनीकों और तरीकों का उपयोग कर लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। कई बार तकनीकी रूप से जानकार व्यक्ति भी इनके जाल में फंस जाते हैं।

ऐसे में प्रत्येक नागरिक को साइबर अपराध के तौर-तरीकों और उनसे बचाव के उपायों की जानकारी होना बेहद जरूरी है। सात सप्ताह के अभियान से 1.70 करोड़ लोगों तक पहुंचा साइबर सुरक्षा का



अभियान का समापन नहीं,यह एक नई शुरुआत है : साय

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि साइबर जागृति अभियान को किसी निश्चित अवधि तक सीमित नहीं रखा जा सकता। सात सप्ताह का यह अभियान समाप्त जरूर हुआ है, लेकिन साइबर जागरूकता की यह यात्रा आगे भी निरंतर जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार का संकल्प प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षित और भयमुक्त वातावरण उपलब्ध कराना है। इसके लिए पुलिस और प्रशासन के साथ सामाजिक संस्थाओं,शैक्षणिक संस्थानों,युवाओं और आम नागरिकों को भी सक्रिय भागीदारी निभानी होगी। विशेष रूप से युवाओं को साइबर जागरूकता के संवाहक के रूप में आगे आकर अपने परिवार और समाज को सुरक्षित बनाने में योगदान देना चाहिए।

संदेश मुख्यमंत्री साय ने छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक चलाए गए सात सप्ताह के विशेष अभियान की सराहना

नहीं सहेंगे। नगर पालिक निगम रायपुर के अंतर्गत संचालित गैठानों की स्थिति दिनों-दिन बदतर होती जा रही है। शहर में घूमंतू मवेशियों का जमघट लगा है। वहीं गैठान संचालित करने वाली संस्थाएं बकाया भुगतान न मिलने से आर्थिक तंगी झेल रही हैं। पिछले कई महीनों से निगम द्वारा गैठान संचालकों को भुगतान नहीं किया गया है। इससे सूखा-खा चारा,दाना और पानी की व्यवस्था करना मुश्किल हो गया है। पर्याप्त चारे के अभाव में मवेशियों का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है संचालकों की प्रमुख समस्याएं लंबित भुगतान और सुविधाओं का अभाव है। फंड न मिलने से कर्मचारियों और चरवाहों का मानदेय तक नहीं दिया जा पा रहा। संचालकों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द बकाया भुगतान और व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो वे गैठान संचालन बंद करने और उठा आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। उन्होंने महापौर और निगम आयुक्त से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की।



लेकिन कोई सुधार नहीं हुई है। गैठानों की हालत सही नहीं है। 250 की क्षमता में कहीं 500 तो कहीं 800 से ज्यादा मवेशी हैं। सड़कों पर मौत हो रही है। कम जगह होने की वजह से गैठान सुरक्षित नहीं। हम सिर्फ सुरक्षित जगह और खाना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ संत समाज के प्रदेश अध्यक्ष राजेश्वरानंद महाराज ने कहा कि पहली रोटी गाय को देनी चाहिए,लेकिन यहां सारी रोटी अंदर हो रही है। इसलिए आज हम आए हैं। यह अन्याय

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती परीक्षा पर लगाई रोक

दिव्यांगों के आरक्षण में गड़बड़ी का आरोप,सरकार से मांगा जवाब

बिलासपुर,09 अक्टूबर 2026।

छत्तीसगढ़ में शिक्षक और सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस कृष्णराम महापात्र की डिवीजन बेंच ने भर्ती विज्ञापन में दिव्यांगों के आरक्षण में गड़बड़ी के आरोप पर यह आदेश दिया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि पूरी तरह दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को आरक्षण के लाभ देने की व्यवस्था नहीं की गई। इससे वे भर्ती में शामिल होने के अवसर से वंचित हो गए। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बता दें कि कुल 2,292 पदों पर भर्ती की जानी है। इन पदों को 2 संवर्गों में बांटा गया है। ई-संवर्ग में 795 पद हैं, जबकि टी-संवर्ग में 1,497 पद हैं। सहायक शिक्षक पद के लिए लिखित परीक्षा 11 अक्टूबर को और शिक्षक पद के लिए परीक्षा 25 अक्टूबर को आयोजित होनी थी। अब हाईकोर्ट की रोक के बाद परीक्षा कार्यक्रम प्रभावित हुआ है। अब भर्ती प्रक्रिया आगे कैसे बढ़ेगी,यह मामले में होने वाली अगली कार्रवाई और अदालत के निर्देशों पर निर्भर करेगा। वहीं अभ्यर्थियों को 11 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा की स्थिति को लेकर अधिकारिक सूचना का इंतजार है। दरअसल,राज्य



पूरी तरह दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को लाभ नहीं देने का आरोप

याचिकाकर्ताओं के वकील ने कोर्ट को बताया कि भर्ती विज्ञापन में दिव्यांगों के आरक्षण से जुड़े नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया गया है। उन्होंने सामान्य प्रशासन विभाग और समाज कल्याण विभाग के सर्कुलर का हवाला देते हुए कहा कि पूरी तरह दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई। इससे ऐसे अभ्यर्थियों के शिक्षक और सहायक शिक्षक बनने के अवसर प्रभावित हुए हैं।

सविधान से मिले अधिकारों के खिलाफ बताया गया

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि भर्ती में दिव्यांगों के लिए पद आरक्षित किए गए हैं,लेकिन पूरी तरह दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को इसका लाभ देने का प्रावधान नहीं है। वहीं,दिव्यांगों की दूसरी श्रेणियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। याचिका में इसे समान अवसर और सविधान से मिले अधिकारों के खिलाफ बताया गया है।

सरकार ने शिक्षक और सहायक शिक्षक पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। इसकी शर्तों और दिव्यांगों के लिए आरक्षण के नियमों को चुनौती देते

हुए कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस कृष्णराम महापात्र की डिवीजन बेंच में हुई।

+ छत्तीसगढ़ में 18 आईपीएस अफसरों का तबादला

अमन कुमार बने एसपी (एसआईए),अजय को एसपी (एसआईबी) की जिम्मेदारी,अशिका जैन जगदलपुर सीएसपी बनीं

रायपुर,09 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ सरकार ने शुक्रवार को 18 आईपीएस और राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों के तबादले का आदेश जारी किया है। गृह (पुलिस) विभाग की ओर से जारी आदेश में 2021 से 2024 बैच तक के अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। इनमें कई अधिकारियों को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एसपी), नगर पुलिस अधीक्षक (सीएसपी) और सहायक पुलिस महानिरीक्षक के पद पर पदस्थ किया गया है। सभी तबादले तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

पुलिस मुख्यालय में इन अधिकारियों की पदरिंज

बीजापुर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ऑप्स) रहे अमन कुमार रमन कुमार को पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर में पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। नारायणपुर में पदस्थ अजय कुमार को पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी दी गई है। आकाश श्रीमाल को सहायक पुलिस महानिरीक्षक (अ.अ.वि.), जबकि अश्वय प्रगोद सबदा को सहायक पुलिस महानिरीक्षक (योजना/प्रबंध) बनाया



गया है। एसटीएफ बधेरा, दुर्ग में पदस्थ आकाश कुमार शुक्ला को सहायक पुलिस महानिरीक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीजापुर में पदस्थ रविन्द्र कुमार मीणा को पुलिस अधीक्षक (चिटफंड एवं महिला विरुद्ध अपराध) बनाया गया है। वहीं,सुकमा में पदस्थ रोहित कुमार शाह को 15वॉहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल,बीजापुर का सेनानी नियुक्त किया गया है।

कई जिलों में एसपी (ऑप्स) की नई पदस्थापना : जगदलपुर के नगर पुलिस अधीक्षक रहे सुमीतकुमार दत्ताहारी को एसएसपी (ऑप्स),कांकर बनाया गया है। रायपुर में सहायक पुलिस आयुक्त रहे ईशू अग्रवाल को एसएसपी (ऑप्स),नारायणपुर की जिम्मेदारी दी गई है। रायगढ़ के नगर पुलिस अधीक्षक मयंक मिश्रा को एसएसपी

प्रशिक्षु अधिकारियों को भी मिली नई जिम्मेदारी

प्रशिक्षु आईपीएस अशिका जैन को नगर पुलिस अधीक्षक,जगदलपुर बनाया गया है। वहीं,प्रशिक्षु अधिकारी साकोर मानसी नानाभाउ को सहायक पुलिस आयुक्त, आजाद चौक,रायपुर नगरीय की जिम्मेदारी दी गई है। राज्य पुलिस सेवा के प्रशिक्षु अधिकारी आदित्य कुमार को नगर पुलिस अधीक्षक,राजनांदागांव और प्रतीक बंसोड़े को नगर पुलिस अधीक्षक, अंबिकापुर नियुक्त किया गया है।

सिरगिट्टी में खेल मैदान के लिए 13 करोड़ रुपए मंजूर बिल्हा विधायक कौशिक की पहल पर मिली स्वीकृति

बिलासपुर,09 अक्टूबर 2026। बिलासपुर के सिरगिट्टी के बन्नाक चौक के पास खेल मैदान और व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए करीब 13 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इससे क्षेत्र के खिलाड़ियों को क्रिकेट समेत दूसरे खेलों के अभ्यास और प्रतियोगिताओं के लिए बेहतर सुविधा मिल सकेगी। मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के तहत यह राशि मंजूर की गई है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अवर सचिव ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। दरअसल, सेकेंड इनिंग क्रिकेट कमेटी के सदस्यों ने हाल ही में सिरगिट्टी में व्यवस्थित खेल मैदान

बनाने की मांग बिल्हा विधायक धरमलाल कौशिक के सामने रखी थी। कमेटी के सदस्यों ने बताया था कि क्षेत्र के युवाओं और खिलाड़ियों में क्रिकेट सहित दूसरे खेलों को लेकर काफी रुचि है, लेकिन अभ्यास के लिए अच्छी सुविधाओं वाला स्थायी मैदान नहीं है। इस मांग पर विधायक धरमलाल कौशिक ने प्रतिनिधिमंडल की मौजूदगी में उपमुख्यमंत्री अरुण साव से फोन पर बात की और सिरगिट्टी में खेल मैदान बनाने का प्रस्ताव रखा। इसके बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उपमुख्यमंत्री अरुण साव से इस काम के लिए स्वीकृति देने का आग्रह किया गया।

करते हुए कहा कि इस अभियान ने साइबर सुरक्षा के संदेश को शहरों से लेकर गांवों तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य किया है।

उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान प्रत्येक सप्ताह अलग-अलग विषयों को केंद्र में रखकर अभिनव गतिविधियां आयोजित की गईं।

विरचविद्यालयों, महाविद्यालयों, विद्यालयों, ग्राम पंचायतों, हाट-बाजारों और सार्वजनिक स्थलों तक पहुंचकर नागरिकों को जागरूक किया गया। अभियान के दौरान 5 लाख से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए,5 लाख से अधिक सेरेफ़ी की माध्यम से नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित की गई और लगभग 1 करोड़ 70 लाख लोगों तक साइबर अपराधों से बचाव का संदेश पहुंचाया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी यह दर्शाती है कि साइबर सुरक्षा अब केवल तकनीकी विषय नहीं, बल्कि प्रत्येक परिवार और नागरिक से जुड़ा विषय बन चुका है।

दूरस्थ क्षेत्रों को परिवहन से जोड़ रही मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा

मुख्यमंत्री साय ने प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं के विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में आगमन की सुविधा विकास की बुनियादी आवश्यकता है। सार्वजनिक परिवहन के साधन उपलब्ध नहीं होने के कारण पहले ग्रामीणों को शिक्षा, स्वास्थ्य, बाजार और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। उन्होंने कहा कि इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा प्रारंभ की गई है। विशेष रूप से वर्षा तक नवसलवाद से प्रभावित रहे बस्तर सहित दूरस्थ क्षेत्रों में बस सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है।ऐसे मार्गों पर 100 से अधिक बसों का संचालन किया जा रहा है, जहां आर्थिक रूप से लाभकारी नहीं होने के कारण पहले बस सेवाएं उपलब्ध नहीं थीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने लाभ-हानि से ऊपर उठकर जनहित को प्राथमिकता दी है और इन मार्गों पर बस संचालन से होने वाली आर्थिक क्षति की भरपाई की व्यवस्था की है। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों के साथ बस में यात्रा के दौरान उन्होंने स्वयं देखा है कि यह सेवा किस तरह लोगों के जीवन में सुविधा और सुशियां लेकर आई है।

डिजिटल लेनदेन में भारत की अग्रणी भूमिका, सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण : उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा

उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि आज दुनिया में होने वाले डिजिटल लेनदेन का लगभग 50 प्रतिशत भारत में हो रहा है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया अभियान की बड़ी उपलब्धि है। डिजिटल लेनदेन ने लोगों के जीवन को सुविधाजनक बनाया है,लेकिन इसके साथ साइबर अपराधों से सुरक्षा की चुनौती भी बढ़ी है। उन्होंने कहा कि नागरिकों को साइबर अपराधों से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से प्रतीसगढ़ पुलिस ने साइबर जागृति अभियान के माध्यम से अभिनव फैल की है। अभियान के दौरान पुलिस ने धार्मिक आयोजनों,चौक-चौराहों,ग्राम सभाओं,ग्राम पंचायतों, विधिविद्यालयों,महाविद्यालयों और विद्यालयों तक पहुंचकर लोगों को ऑनलाइन ठगी तथा साइबर अपराधों से बचाव के तरीके बताए।